▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

वैशाख—ज्येष्ठ 2081, मई 2024

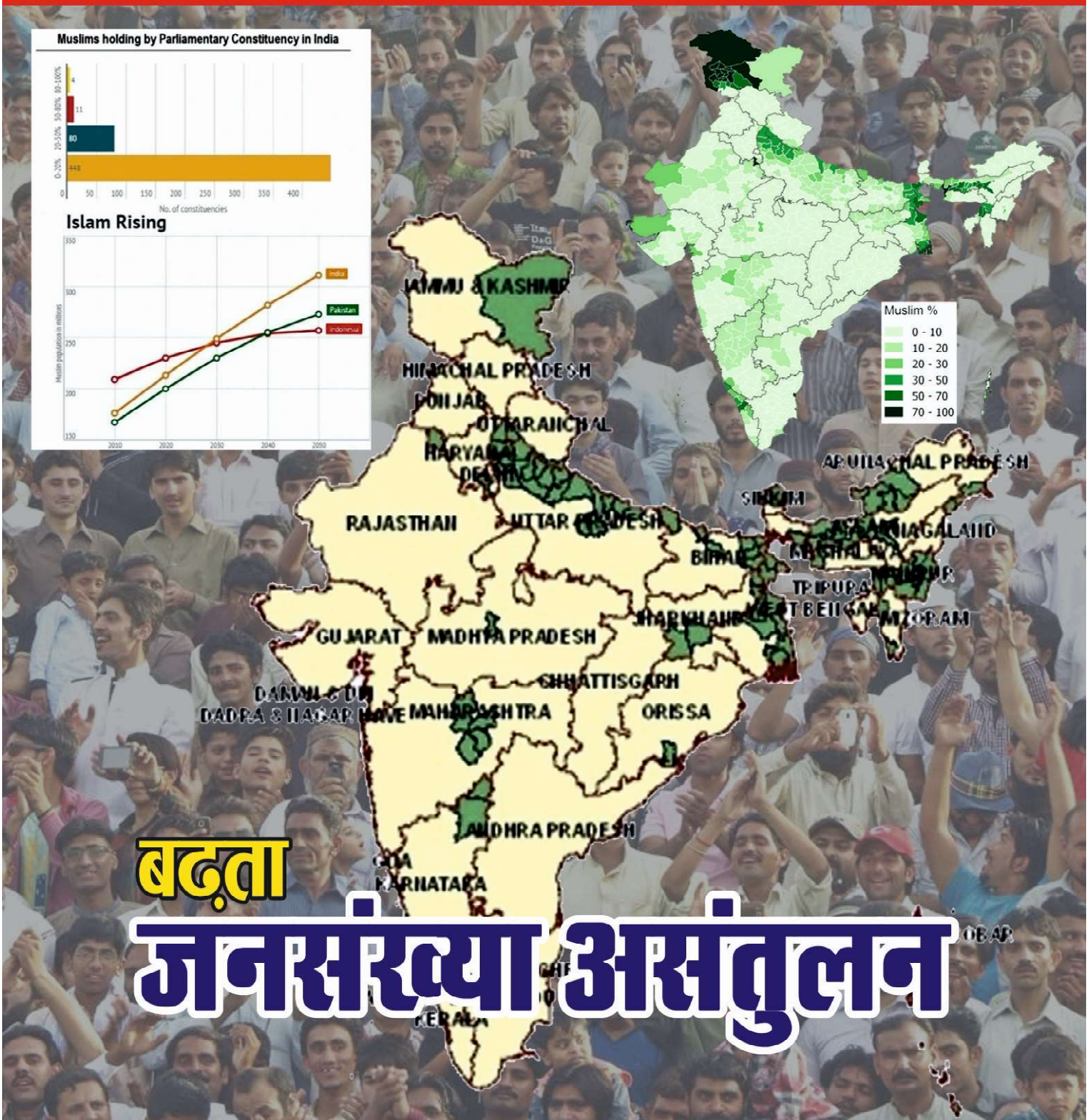

बढ़ता जनसंख्या असंतुलन

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सीतापुर, अवध

रायपुर, छत्तीसगढ़

रोहतक, हरियाणा

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–32, अंक–5
वैशाख–ज्येष्ठ 2081 मई 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

जनसंख्या असंतुलन

डॉ. अश्वनी महाजन

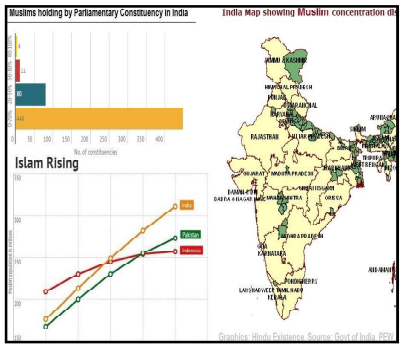

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा–2
राष्ट्रहित में नहीं – जनसंख्या असंतुलन
अनुपमा अग्रवाल

11 मुद्दा
पैकेज्ड फूड की वैश्विक जांच
के.के. श्रीवास्तव

13 पर्यावरण
तपती धरती के लिए जिम्मेवार है इंसानी हरकतें
अनिल तिवारी

15 बहस
कब तक टिकेगा चुनावी रेवड़ियों का अर्थशास्त्र?
विक्रम उपाध्याय

17 आजकल
खटाखट योजनाओं का नुकसान
शिवनंदन लाल

19 विमर्श
जीएमओः जैव– साम्राज्यवाद
वंदना शिवा

21 आर्थिकी
स्थिर और मजबूत रुपये की आहट
स्वदेशी संवार्द

23 आर्थिकी
आर्थिक क्षेत्र में नित नए विश्व रिकार्ड बनाता भारत
प्रहलाद सबनानी

25 कृषि
किसानों पर शिकंजे जैसा है 'फ्री ट्रेड' फार्मूला
देविन्दर शर्मा

27 विश्लेषण
समृद्धि स्वदेश में, फिर क्यों जा रहे परदेस में?
विनोद जौहरी

29 जल प्रबंधन
रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

31 पर्यावरण
प्रकृति केन्द्रित विकास की अवधारणा
प्रो. विजय वशिष्ठ

34 बैंकिंग
अमेरिकी बैंक क्यों हो रहे दिवालिया?
स्वदेशी संवाद

पाठकनामा

स्वावलंबी भारत अभियान का उद्देश्य

स्वावलंबी भारत अभियान जिस उद्देश्य के लिए प्रारभं हुआ था, उसका असर देश में देखने को मिल रहा है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने भारत के विकास की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। यह अकड़ा भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छे रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह शुद्ध व पौष्टिक भोजन और रहने के लिए घर, कपड़ें आदि की व्यवस्था कर सके। स्वावलंबी भारत अभियान देश से गरीबी हटाने और उद्यमिता को बढावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम करता है, जिसमें युवाओं को रोजगार, उद्यमिता, स्वरोजगार आदि विषयों के लिए प्रेरित करना है। अभी तक देश भर में 10 लाख से अधिक युवाओं को कॉलेज और स्कूलों में जाकर प्रेरित किया जा चुका है। इसके अलावा देश के 460 जिलों में युवाओं की मदद के लिए स्वावलंबन केंद्र की स्थापना भी की है, जिसमें समय–समय पर नए उद्यम करने के लिए विभिन्न तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है और मधुमक्खी पालन, कूड़े से थैली, बेकरी आदि विषयों पर जानकारी देकर रूचि अनुसार युवाओं को अपना–अपना रोजगार खोलने में मदद करते है, ताकि वह किसी के पास नौकरी न कर, खुद का मालिक स्वयं बन सकें और मेहनत के मुताबिक अधिक लाभ भी कमा सके।

भारत को पूर्ण रोजगारयुक्त और गरीबीमुक्त बनाने के उद्देश्य के साथ स्वावलंबी भारत अभियान लगातार काम करता रहेगा और उम्मीद है कि सरकार और जन अभियानों के प्रयासों से यह लक्ष्य जल्द पूरा होगा तथा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलायेगा।

विजित कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारतीय डॉक्टरों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। सस्ती चिकित्सा सेवा के कारण भारत चिकित्सा पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।

द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

दुनिया में जहां हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है, भारत को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी बुनियादी जरूरतें और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो। इसीलिए 'मेक इन इंडिया' महत्वपूर्ण है।

एस. जयशंकर, विदेशी मंत्री, भारत

हम अन्य देशों को प्रेरित करने और हर किसी से सीखने और अपनी डिजिटल प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की उम्मीद करते हैं। हमारा मानना है कि पृथ्वी को अधिक समावेशी और समृद्ध ग्रह बनाने की हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अश्वनी वैष्णव, संचार एवं आईटी मंत्री, भारत

वित्त प्रकृति में अत्यधिक गतिशील है। विरासत कर की प्रत्याशा में यदि लोग अपनी मृत्यु के बाद अपनी संतानों पर विरासत पर लगने वाले उच्च कर से बचने के लिए अपनी संपत्ति विदेश स्थानांतरित करते हैं, तो हम राष्ट्रीय संपत्ति को विदेशी देशों के हाथों खो देंगे। वह सबसे खराब स्थिति होगी।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

औद्योगिक निवेश बढ़ने से घटेंगे चीनी आयात

सर्वविदित है कि चीनी आयात पर भारत की निर्भरता लंबे समय से बढ़ रही है, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग विऔद्योगिकीकरण हो गया, जहां हमारे अधिकांश उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनमें से कई को बंद करना पड़ा। 2003–04 में चीन से आयात मुश्किल से 4.05 बिलियन डॉलर था; जो 2013–14 तक बढ़कर 51.1 बिलियन डॉलर हो गया, जो सालाना लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस समस्या को समझते हुए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने पहले मेक इन इंडिया और फिर मई 2020 से कोविड–19 के मध्य सुविचारित 'आत्मनिर्भर भारत' का विचार सामने रखा। उल्लेखनीय है कि चीनी माल का आयात जो यूपीए के दशक में हर ढाई साल में दोगुना हो रहा था, उसकी वृद्धि दर मोदी सरकार के पहले छः साल में घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई। हालाँकि मई 2020 के बाद भी चीनी आयात में वृद्धि जारी रही, इसके पीछे अन्य कई कारण थे। मई 2020 के बाद से जब हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की नीति का पालन किया, तो एक बड़ी उम्मीद जगी कि हम चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे और विनिर्माण क्षेत्र को पटरी पर ला सकेंगे और चीनी निर्भरता से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिमों से भी बच सकेंगे। लेकिन, चीनी आयात पर निरंतर और बढ़ती निर्भरता के बारे में हालिया रिपोर्टों ने न केवल आत्मनिर्भर भारत की प्रभावशीलता के बारे में, बल्कि चीनी आयात से जुड़े सुरक्षा और आर्थिक जोखिमों के बारे में भी चिंता जताई है। उल्लेखनीय रूप से, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट ने हाल ही में खुलासा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और विद्युत उत्पादों के कुल आयात का 56 प्रतिशत हिस्सा चीन और हांगकांग से है। दूसरे जीटीआरआई ने कहा है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है, जहां चीन के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 2023–24 में 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि यूएसए के साथ यह 118.3 बिलियन डॉलर है। इस द्विपक्षीय व्यापार में चीनी आयात का हिस्सा 101 बिलियन डॉलर है, जबकि निर्यात केवल 17 बिलियन डॉलर के हैं। हालांकि आयात का यह आंकड़ा चौंका देने वाला लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि एनडीए शासन के दौरान चीनी आयात की वृद्धि दर सालाना केवल 7.0 प्रतिशत रही है, जबकि यूपीए शासन के दौरान 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी।

गौरतलब है कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह भी सच है कि नीति की घोषणा और उसके परिणाम के बीच हमेशा एक अंतराल होता है। हम विनिर्माण के क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं, जो हमें आने वाले वर्षों में चीन पर निर्भरता कम करने की उम्मीद देता है। उदाहरण के लिए, आइए सबसे पहले फार्मा और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) का उदाहरण लेते हैं। हम एपीआई और फार्मा में महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण देखते हैं। उदाहरण के लिए, हम देखते हैं कि पीएलआई के लिए पहचाने गए 12 श्रेणियों के सामानों में एपीआई भी शामिल थे। एपीआई क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना में 41 उत्पाद शामिल हैं, जिनमें मधुमेह, तपेदिक, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक दवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2023 तक पीएलआई योजना के तहत फार्मा कंपनियों को एपीआई में करीब 4,000 करोड़ रुपये और मेडिकल उपकरणों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा केंद्र ने 3,000 करोड़ रुपये की लागत से तीन बल्क ड्रग पार्क विकसित किए हैं। चीन द्वारा हमारी निर्भरता और कमजोरी का फायदा उठाने के कारण कीमतें आसमान छू रही थीं, जो अब कम होने लगी हैं। विशेषज्ञों का मानना घ्है कि भारत में एपीआई के उत्पादन में वृद्धि के कारण पिछले कुछ महीनों में चीन का 'ड्रग्स कार्टेल' टूट गया है। आयात में कमी के अलावा बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है 2022–23 में भारत ने 2022–23 में 37853 करोड़ रुपये के बल्क ड्रग्स और ड्रग्स इंटरमीडिएट्स का निर्यात किया, जो इस श्रेणी के 25,552 करोड़ रुपये के आयात से 12,302 करोड़ रुपये अधिक है। रसायनों के मामले में भी भारत कमोबेश आत्मनिर्भर है और निर्यात में भी तेजी आ रही है। इसके अलावा भारत के रक्षा सामानों के निर्यात में भी उछाल आया है। भारत बड़ी और छोटी बंदूकें, राइफलें, मिसाइलें और कई अन्य सहित सबसे उन्नत रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। जहाँ 2004–05 से 2013–14 के बीच भारत का रक्षा निर्यात मुश्किल से 4312 करोड़ रुपये था, वहीं 2014–15 से 2023–24 के बीच भारत का रक्षा निर्यात 88319 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है (यानि 21 गुना वृद्धि)। एक ही वर्ष 2023–24 में रक्षा निर्यात 21083 करोड़ रुपये (लगभग 2.63 अरब अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है।

देश में विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के प्रयासों से ऐसा संभव हो पा रहा है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आईआईपी) ने 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। घरेलू उद्योग के लिए चीनी मध्यवर्ती और घटकों पर निर्भरता को देखते हुए, चीनी आयात में वृद्धि इस वृद्धि का एक स्पष्ट परिणाम था। ऑटोमोबाइल और सहायक उद्योग में पिछले तीन वर्षों में लगभग 1. 28 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा हुई है, जो उससे तीन साल पहले की घोषणा से लगभग 6 गुना अधिक है। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में 2021–22 और 2023–24 के बीच पिछले तीन वर्षों में कुल 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा हुई है, जो उससे पिछले तीन वर्षों की घोषणाओं से 102 गुना अधिक है। दवा और फार्मा उद्योग को देखें, तो पाते हैं कि 2018 से पहले शायद ही कोई नये निवेश की घोषणा हुई थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में हम 18,112 करोड़ रुपये की घोषणा देखते हैं, जो उससे तीन साल पहले की घोषणा से 15.5 गुना अधिक है; इसी तरह, खाद्य उद्योग में भी निवेश के संबंध में 23,484 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जो उससे तीन साल पहले की घोषणा से 8 गुना अधिक है। हालांकि भारत अभी भी बड़ी मात्रा में चीनी सामान आयात करता है, जिसमें आम तौर पर मध्यवर्ती और घटक शामिल होते हैं, जिससे भारत को उनकी मदद से निर्मित उत्पादों को निर्यात करने में मदद मिलती है, लेकिन वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर चल रही है और चीनी और आयातित उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए कई उपाय अपना रही है। हम कह सकते हैं कि संभावनायें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। साथ ही मोबाइल फोन, रक्षा उत्पाद, खिलौने, रसायन और दवा उत्पादों का बढ़ता निर्यात इस बदलाव का गवाह है, जो चीनी आयात पर निर्भरता के कम होने का सूचक है।

जनसंख्या असंतुलन

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, 1950 से लेकर 2015 तक कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कई अन्य देशों में भी, जहां बहुसंख्यक आबादी गैर–मुस्लिम थी, उसकी हिस्सेदारी में कमी आई है और अल्पसंख्यक आबादी जो मुस्लिम है, की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह प्रवृत्ति म्यांमार और नेपाल में भी देखी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहां मुस्लिम खुद बहुसंख्यक हैं, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। यानि सवाल अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ने का नहीं, बल्कि दुनिया में मुस्लिम आबादी बढ़ने का है, जिसका असर यूरोप समेत दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा रहा है।

जनसंख्या संतुलन प्राप्त करने और आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मानकों के दृष्टिकोण से भविष्य की जनसंख्या को उन्नत करने के लिए जनसंख्या नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परिवार को सीमित करने हेतु कुछ क़ानूनी प्रावधान भी इस दिशा में समाधान दे सकते हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

अगर बात सिर्फ भारत की करें तो जहां 1950 में हिंदुओं की आबादी का हिस्सा 84. 68 प्रतिशत था, वो 2015 तक घटकर सिर्फ 78.06 प्रतिशत रह गया, जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1950 में 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 14.09 प्रतिशत हो गया। गौरतलब है कि भारत की कुल जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2015 में 132.29 करोड़ हो गई और इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी समुदायों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ख़ास बात यह है कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर अन्य सभी जातीय समूहों से ज्यादा रही है। जबकि, हिंदू आबादी 1951 में 30.57 करोड़ से बढ़कर 2001 में 82.75 करोड़ हुई (यानि 2.0 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर); मुस्लिम आबादी 3.55 करोड़ से बढ़कर 13.8 करोड़ हो गई (2.75 प्रतिशत की भारी वार्षिक वृद्धि दर); सिखों की जनसंख्या 0.69 करोड़ से बढ़कर 1.94 करोड़ हो गई और ईसाइयों की जनसंख्या 0. 83 करोड़ से बढ़कर 2.41 करोड़ हो गई, यानि 50 वर्षों में क्रमशः 2.09 प्रतिशत और 2.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर। कुछ लोगों का तर्क है कि पिछले दो दशकों में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो गई है। हालांकि, यह सच है कि 2001 से 2015 के बीच विभिन्न जातीय समूहों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है; लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि अभी भी अन्य धार्मिक समूहों से बहुत आगे है। हम देखते हैं कि वर्ष 2001 और 1015 के बीच हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 1.61, 2. 17, 1.68 और 1.82 रही।

इस रिपोर्ट से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों को दबाया और सताया जाता है। लेकिन आंकड़े इस नैरेटिव को पूरी तरह से नकारते हैं।

भारत की जनसांख्यिकी में सामान्य परिवर्तन

गौरतलब है कि भारत में 1951 में कुल प्रजनन दर 5.9 थी, जो 1981 में घटकर 4.80 और 2011 में 2.56 हो गई। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत में कुल प्रजनन दर 2.12 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि जनसांख्यिकी सिद्धांत के अनुसार, जब किसी देश की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे गिरती है, तो उस देश की जनसंख्या कुछ समय बाद घटने लगती है। इसलिए प्रजनन दर का 2.12 तक पहुंचना जनसंख्या के लिए खतरे की घंटी है।

पिछले कुछ समय से भारत में कुल प्रजनन दर में लगातार गिरावट के कारण अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां से कुछ समय बाद वास्तविक जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि चीन में ऐसी स्थिति पहले ही आ चुकी है। यूरोप के कई देश भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। अफ्रीका के बाद भारत भी उन चंद देशों में शामिल है, जहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब भारत में भी जनसंख्या में कमी आने की आशंका जताई जा रही है।

लेकिन ऐसे में पीएमईएसी की रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भले ही आने वाले समय में कुल जनसंख्या में कमी आएगी, लेकिन उसमें भी हिंदुओं की जनसंख्या, जो पहले से ही आनुपातिक रूप से कम हो रही है, इसमें निरपेक्ष रूप में भी कमी होनी शुरू हो सकती है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। हम कह सकते हैं कि हिंदू जनसंख्या के नुकसान की भरपाई मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि से होगी।

शिक्षित वर्ग की जनसंख्या में गिरावट की संभावना

जनगणना और अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि निरक्षर और कम शिक्षित महिलाओं में कुल प्रजनन दर 2011 में 3.17 रही। लेकिन स्नातक या उससे ऊपर की महिलाओं में प्रजनन दर जो 1991 में 1.62 थी, 2011 में घटकर 1.40 रह गई और अभी भी इसमें और गिरावट की पूरी संभावना है। इसी तरह, स्नातक से कम शिक्षित अन्य महिलाओं में भी प्रजनन दर अपेक्षाकृत कम होती है।

यदि हम शिक्षा के मामले में विभिन्न धार्मिक समूहों की तुलना करें, तो यह स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय अभी भी हिंदुओं की तुलना में कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है और इसलिए संभावना है कि मुस्लिम आबादी में वृद्धि जारी रहेगी, जबकि हिंदू आबादी में गिरावट आ सकती है। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, हिंदुओं में साक्षरता दर 65.8 प्रतिशत थी, जबकि मुसलमानों में यह केवल 59.1 प्रतिशत थी। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो हम देखते हैं कि 2001 में 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में मुस्लिम समुदाय में स्नातक और अधिक शिक्षित लोगों की संख्या केवल 6.7 प्रतिशत थी, जबकि हिंदुओं में यह 12.5 प्रतिशत थी। शिक्षा और कुल प्रजनन दर के बीच संबंधों को देखते हुए, हम सहज रूप से कह सकते हैं कि कम शिक्षित मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि अधिक शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम होती है। यानि मुस्लिम आबादी में वृद्धि और हिंदू आबादी में कमी को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शिक्षा के स्तर में अंतर से भी समझाया जा सकता है।

संतुलन कैसे लाया जाए?

एक आम धारणा है कि मुसलमान अपनी परंपराओं, दर्शन और धार्मिक मान्यताओं के कारण बड़े परिवार रखते हैं। अतीत में गरीब हिंदू भी यह मानते थे कि बच्चे भगवान की देन हैं, लेकिन अधिकांश मुसलमान अपने आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण अभी भी उसी पर विश्वास करते हैं (यानी बच्चे अल्लाह की देन हैं)।

हमने देखा है कि आर्थिक समृद्धि, शैक्षिक विकास और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर सभी में कमी आ रही है। विभिन्न धार्मिक समूहों में शैक्षिक और आर्थिक मानकों में अंतर भी विभिन्न जातीय समूहों में प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि में अंतर को स्पष्ट करता है।

जनसंख्या असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। जनसंख्या संतुलन के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हो सकते हैं:–

सबसे पहले, हमारी आबादी, विशेष रूप से मुस्लिम आबादी को शैक्षिक रूप से उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे कुल प्रजनन दर और इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में मदद मिल सकती है।

दूसरा, अभी भी एक संभावना हो सकती है कि जब तक हम उच्च शिक्षा मानकों तक नहीं पहुंच जाते, या उसके बाद भी धार्मिक मान्यताओं और मनोविज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि जारी रहे; इससे निपटने के लिए हम जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और हतोत्साहन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पिछले कुछ समय से जनसंख्या नीति पर बहस चल रही है। जनसंख्या संतुलन प्राप्त करने और आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मानकों के दृष्टिकोण से भविष्य की जनसंख्या को उन्नत करने के लिए जनसंख्या नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परिवार को सीमित करने हेतु कुछ क़ानूनी प्रावधान भी इस दिशा में समाधान दे सकते हैं। ❑❑

राष्ट्रहित में नहीं - जनसंख्या असंतुलन

2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जनसंख्या वाले देश भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर जगह बना ली है।जबकि 2024 तक यह जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। भारत की आबादी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों में बहुसंख्यक आबादी में आये परिवर्तन का अध्ययन करके पाया कि 1950 से 2015 के बीच भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82 प्रतिशत घट गई है जबकि इस बीच मुसलमानों की हिस्सेदारी में 43.25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुस्लिम बहुल देशों में इसके विपरीत अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी में भारी गिरावट दर्ज की गई है वहीं भारत में ईसाई और सिख अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी में क्रमशः 5.38 प्रतिशत और 6.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि पारसी और जैन अल्पसंख्यक हिस्सेदारी कम हुई है। यही नहीं लगभग सभी मुस्लिम राष्ट्रों में हिंदुओं की संख्या में पहले की अपेक्षा कमी देखी गई है। हिंदुत्व पर मंडरा रहे गहरे संकट को दर्शाते ये आंकड़े हिंदुओं की वृद्धि दर में गिरावट तथा मुस्लिमों की वृद्धि दर में बढ़ोतरी का परिणाम है।यही कारण था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव से भारत में समान नागरिक कानून लागू करने का पक्षधर रहा है। भारत में जनसंख्या का असंतुलन जिस गति से बढ़ रहा है शीघ्र ही यह भारत की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पहचान पर संकट पैदा कर सकता है तथा बढ़ती मुस्लिम आबादी राष्ट्र के भविष्य और समाज के अस्तित्व के लिए घातक हो सकती है क्योंकि हमारे जिन पूर्वजों ने इस सभ्यता और संस्कृति को सींचा और बढ़ाया उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सीमा पार से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों का देश में आगमन एवं धर्म परिवर्तन भी जनसंख्या असंतुलन का अहम कारण है। इसके अलावा आर्थिक रूप से देश के संसाधनों का दोहन करती ये आबादी न केवल देश पर अतिरिक्त भार डाल रही है बल्कि ज्यादा संख्या में होने के कारण मुस्लिम आबादी देश में अराजकता का माहौल पैदा करने में अहम भूमिका निभा रही है।

विस्फोटक रूप धारण करती जनसंख्या असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार को ऐसी सार्वभौमिक जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है जो सभी धार्मिक समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों पर समान रूप से लागू हो।

–अनुपमा अग्रवाल

भारत में 1872 से जनगणना आरम्भ हुई, तभी से पंथानुसार आंकड़े एकत्र किए जाते रहे थे सामाजिक, आर्थिक विषयों का पंथ, शिक्षा, लिंग,आर्थिक व्यवसाय आदि के अनुसार

विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता था परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंथानुसार जनगणना को बंद कर दिया गया। 2001 में पुनः इस आधार पर जनगणना के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण कर व्यवसाय, लिंग, शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। धर्माधारित जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2001–2021 के बीच देश में मुस्लिम आबादी 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गई है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां बहुसंख्यक आबादी में कमी देखी गई वहीं अल्पसंख्यकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में 80.61 फीसदी हिन्दू थे और 18.50 फीसदी मुसलमान थे लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73 प्रतिशत और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 19.26 प्रतिशत हो गई। जनगणना विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यही स्थिति मिजोरम, नगालैण्ड, मेघालय, केरल, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि राज्यों में है जहां हिन्दू अल्पसंख्यक है और यहां ईसाई या फिर मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा है। अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य से हासिल क्या होने वाला है? जनसंख्या असंतुलन या जनसांख्यिक परिवर्तन किसी भी समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनने के साथ राष्ट्रीय पहचान पर संकट पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इसके लिए किसी बाहरी उदाहरण की आवश्यकता नहीं, भारत स्वयं 1947 में जनसांख्यिक असंतुलन के कारण विभाजन की दुखद त्रासदी को झेल चुका है।

इतिहास साक्षी है कि जिन राज्यों

जनसंख्या असंतुलन या जनसांख्यिक परिवर्तन किसी भी समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनने के साथ राष्ट्रीय पहचान पर संकट पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इसके लिए किसी बाहरी उदाहरण की आवश्यकता नहीं, भारत स्वयं 1947 में जनसांख्यिक असंतुलन के कारण विभाजन की दुखद त्रासदी को झेल चुका है।

में हिन्दू प्रबल बहुसंख्यक रहे वहां दंगे न के बराबर हुए जबकि मुस्लिम बहुलता वाली स्थानों पर अधिक दंगे देखे गए, जो कि इस्लामीकरण की जड़ हैं। देश के प्रमुख राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के द्वारा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा इस्लाम, न केवल देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है बल्कि देश की कानून व्यवस्था पर अविश्वास दर्शाकर मस्जिदों से फतवे व विभिन्न प्रकार के जिहाद चला कर देश को खण्डित करने का षड्यंत्र रच रहा है। 2020 में दिल्ली में हुए दंगे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बिखराव की स्थिति में कम्युनिस्टों के सहारे खड़ा देश का विपक्ष, वोट बैंक की राजनीति के तहत मुसलमानों को साधने के लिए न केवल उनका समर्थन करता है बल्कि केंद्र द्वारा राष्ट्रहित में जारी एनआरसी, सीएए व जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून को देश में लागू करने का घोर विरोधी होने के साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थक भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री के.सी. सुदर्शन जी ने इस समस्या की गंभीरता को भांपते हुए कहा था कि हिंदुओं की घटती वृद्धि दर सम्पूर्ण भारत के भविष्य के लिए खतरा और आशंकाएं पैदा करती है इसलिए आवश्यक है कि जिन कारणों से राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिक सन्तुलन पर हमला हो रहा है, उन पर गंभीरता से विचार कर समाधान खोजा जाए। सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेश व म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों की सघन आबादी का बढ़ना सभी राष्ट्र भक्तों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह मुद्दा राष्ट्र के भविष्य और उसके अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं की जनसंख्या कम होने का परिणाम आज तक देश के लिए घातक ही सिद्ध हुआ है। अगर हम अब भी नहीं संभले तो हजारों साल से अपने बल, पराक्रम और धैर्य से जिन पूर्वजों ने इस सभ्यता और संस्कृति को सींचा और बढ़ाया, उसका नामोनिशान अंततः मिट जाएगा। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से आव्हान किया कि वे समान नागरिक कानून लागू करने की मांग करें। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत जी ने जनसंख्या असंतुलन की गम्भीरता को भांपते हुए एक "व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति" की आवश्यकता पर जोर दिया और यह सभी पर 'समान रूप से लागू हो' व जनसंख्या असंतुलन पर नजर रखना राष्ट्रीय हित में बताया।

लगातार बढ़ती आबादी जहां संसाधनों पर बोझ बनती जा रही है वहीं इससे उत्पन्न बेरोजगारी के कारण गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण जैसी समस्याएं देश में पनप रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है उसकी आपूर्ति हेतु उतनी ही तीव्रता से प्रकृति के नियमों की अनदेखी कर उनका अतिरिक्त दोहन हो रहा है। विकास की अंधी दौड़, रोजगार सृजन एवं आवास आपूर्ति के कारण खेतिहर भूमि कम हो रही है, जबकि अन्न की मांग बढ़ रही है।इसी तरह बढ़ती आबादी की प्यास बुझाने के लिए पेयजल की मांग बढ़ रही है परन्तु

समरसेबल की अधिकता व जल के अत्यधिक दोहन ने धरती के जल को सुखा दिया है। रही बात शुद्ध प्राणवायु की, तो पेडों के कटान एवं जंगलों के सफाए से जहां ऑक्सीजन कम और प्रदूषण में वृद्धि हो रही है वहीं ये सभी चीजें जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रही हैं जो वर्तमान में विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही नहीं, गंभीर समस्या भी बन चुकी है। अतः देश के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही बढ़ती आबादी को तत्काल नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

गृह मंत्रालय भारत में अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से पैदा होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त कर चुका है। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के रास्ते असम, बंगाल, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू आदि राज्यों में जहां इनका समर्थन करने वाली सरकार मौजूद है, बड़ी मात्रा में फैल कर न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं बल्कि जिन संसाधनों पर भारतवासियों का अधिकार है उनका अधिकाधिक लाभ ये लोग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता के सबूत भी समय समय पर मिलते रहते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2018–2020 के बीच भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करने वाले तीन हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सर्वाधिक संख्या पाकिस्तान व बंगलादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की थी। चौकाने वाली बात यह है कि बहुत से घुसपैठियों ने तो लेन देन और मिलीभगत से अपने राशनकार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिए हैं जिससे इनकी पहचान करना अब और भी मुश्किल हो गया है।

विस्फोटक रूप धारण करती जनसंख्या असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार को ऐसी सार्वभौमिक जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है जो सभी धार्मिक समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों पर समान रूप से लागू हो क्योंकि अतीत के उदाहरण बताते हैं कि जनसंख्या असंतुलन से देश की भौगोलिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। देश के लगभग एक चौथाई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं इसके क्या सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक सौहार्द कैसे प्रभावित होंगे इन प्रश्नों पर आत्म मंथन तथा चर्चा की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार को जनसांख्यिक असंतुलन को कम करने व मतांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने होंगे तथा राष्ट्रहित में सीएए और एनआरसी जैसे कानून को अमली जामा पहनाकर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा ताकि भारत को 1947 में जनसांख्यिकी के असंतुलन के कारण हुए विभाजन जैसी त्रासदी पुनः न झेलनी पड़े। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

पैकेज्ड फूड की वैश्विक जांच

भारतीय मसाला निर्यात उद्योग पर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। हांगकांग, सिंगापुर सहितकुछ देशों ने शीर्ष भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट द्वारा बेचे जाने वाले मसाला मिश्रण में संभावित संदूषण के जांच की घोषणा की है। शिकायतों में मसाले में इथाईलीन ऑक्साइड की मौजूदगी का हवाला दिया गया है जो खाद्य पदार्थ को स्थिर करने वाले के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला एक जहरीला रसायन है जो सीमा से अधिक है। हालांकि अपने आधिकारिक बयान में सरकार ने कहा है की जिन देशों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया है वहां कुल मसाला निर्यात का महज एक प्रतिशत ही भेजा जाता है। अगर समय रहते चीज ठीक नहीं होती है तो मसाला कारोबार के सालाना लगभग 50 हजार करोड रुपए के निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

पैकेज्ड मसाले को लेकर सवाल उठाने वाले सिर्फ दो ही देश नहीं है बल्कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित लगभग पांच देशों ने शिकायतें की है तथा अपने स्तर पर जांच कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके जवाब में भारतीय मसाला बोर्ड ने विदेशों में भेजे जाने वाले उत्पादों का अनिवार्य परीक्षण शुरू कर दिया है और कथित तौर पर संदूषण के मूल कारण की पहचान करने के लिए निर्यातकों के साथ भी काम कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय जांच ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) से घरेलू बाजारों में बेचे जाने वाले मसाले और करी पाउडर पर कड़ी गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने की मांग भी बढ़ा दी है।

सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने अपनी शिकायतों में कहा है कि भारतीय उत्पादों में खतरनाक संदूषक हैं जिससे कुछ प्रकार के कैंसर विकसित होने की संभावना है। दोनों आरोपी कंपनियों ने किसी न किसी तरीके से नियामक अधिकारियों की कार्रवाई को कमतर आंकने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए एमडीएच इथीलीन ऑक्साइड के उपयोग से इनकार करता है, फिर भी क्षेत्र के नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जांच का फैसला किया है। हालांकि एफएसएसएआई ने उन दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि भारतीय जड़ी बूटियां और मसालों में बहुत अधिक कीटनाशक होते हैं।

कड़वी सच्चाई यह है कि खाद्य पदार्थों के लिए निर्धारित मानक काफी व्यापक और सख्त हो सकते हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले नियमों को लागू करना सुरक्षा परीक्षणों के लिए गंभीर रूप से अपर्याप्त है। बुनियादी स्तर पर खेदजनक तथ्य यह है कि सरकार के पास परीक्षण उद्देश्यों के लिए न तो सही और न ही पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं हैं और न ही इस काम को अंजाम देने के लिए पर्याप्त कर्मचारी ही हैं। एक तथ्य यह भी है कि निर्यात नियम अलग–अलग देश में अलग–अलग होते हैं जिनमें कोई सामान्य मानक नहीं होता। ऐसे में निर्यातक कंपनियों को प्रत्येक देश को नियंत्रित करने वाले नियामक पहलुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी जानबूझकर कोई नामी

सरकार को और अधिक मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं बनाने, राज्य सरकार के स्तर पर कार्यशील खाद्य प्रयोगशालाएं सुनिश्चित करने और अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने तथा मानदंडों के कार्य को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

– के.के. श्रीवास्तव

गिरामी कंपनी मिलावटी उत्पाद नहीं बेचना चाहेगी। संभव है कि समस्या ज्ञान अंतर का हो। इतना ही नहीं, यहां तक की परीक्षण पद्धतियों से भी समझौता किया जा सकता है, क्योंकि संबंधित कंपनी मानकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करने में सफल हो सकती है। इसके बाद उसे नमूने को पारित करना पड़ सकता है जिसे मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी।

फिर भी भारतीय मसाले एक बुरी वजह से इस समय सुर्खियों में है। लेकिन यह समस्या केवल निर्यातित मसाले तक ही सीमित नहीं है हाल के दिनों में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर ढेर सारी रिपोर्ट आए दिन मीडिया में छपती रही है। कई तरह के नकली पेय पदार्थ बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जिस तरह विदेश में भारतीय मसाले को लेकर सवाल खड़े हुए हैं वैसे ही भारत में नेस्ले के शिशु आहार उत्पादन में अत्यधिक चीनी के मिलावट के बारे में सवाल उठते रहे हैं। नेस्ले ने इससे इनकार किया है तथा चीनी की मात्रा भारत में स्वीकार्य से कम होना बताया है। अमेरिका ने भारतीय मसाले को कैंसरकारी घोषित कर दिया है जिसके चलते वहां मसाले की आयात दर पिछले एक साल में कम हुई है। यूरोपीय संघ ने भी भारतीय मूल की अच्छी वस्तुओं को जांच के दायरे में रखा है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए यह आशंका पैदा करने वाला है। विवादों से यह भी आशंका पैदा होती है कि भारतीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा कम से कम विनियमन और परीक्षण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हो सकता है या वह जानबूझकर नियामक रडार को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह चिंता सताती रहती है कि उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य उत्पाद सुरक्षित हैं कि नहीं। कारोबार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मिलावट हर जगह देखने को मिलती है कहीं दूध में पानी की मिलावट तो कहीं मसाले में रंगों की, दूध, चाय, चीनी, दाल, अनाज, हल्दी, फल, आटा, तेल, घी आदि ऐसी तमाम तरह की घरेलू उपयोग की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है। पूरे पैसे खर्च करके भी आम आदमी को शुद्ध खाने का सामान नहीं मिल पाता। मिलावट इतनी सफाई से होती है कि असली खाद्य पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। घी के नाम पर चर्बी, मक्खन की जगह मार्गग्रीन, आटे में सेलखड़ी का पाउडर, हल्दी में पीली मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के बीज, कटी हुई सुपारी में कटे हुए छुहारे की गुठलियां मिलाकर बेची जा रही है नकली मावा और नकली दूध का बिकना तो आम बात है। अब तो नकली जीरे का कारोबार भी देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। आज देश दुनिया में जिस तरह कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, उच्च रक्त चाप जैसी अनेक बीमारियां तेजी से फैल रही है तथा चिंताजनक गति से लोगों को गिरफ्त में ले रही हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार बढ़ती संपन्नता हमारे खान–पान और आदतों में बदलाव ला रही है। हम स्वस्थ उत्पादों की ओर झुक रहे हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे पैक किए गए खाद्य पदार्थों में अत्यधिक चीनी मिलाई गई है। इसीलिए स्वास्थप्रद पदार्थ हमें लाभ कम नुकसान अधिक दे रहे हैं।

एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लागू होने के दो साल बाद वर्ष 2008 में की गई थी। यह छोटी, मध्य और बड़ी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सभी कंपनियों के लिए सुरक्षा के मानकों को देखता है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है लेकिन बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी के कारण इसका काम प्रभावित हुआ है। इसने विपदा के एक बड़े वर्ग को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और शोध द्वारा निर्धारित नियामक निरीक्षण के बजाय नियमों को कागजी कार्रवाई के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है। एफएसएसएआई वास्तव में उपभोक्ताओं और व्यवसायियों दोनों को खाद्य सुरक्षा मुद्दों और मानदंडों पर शिक्षित करने के लिए बाध्य है। इसका उद्देश्य भोजन की खपत, जैविक जोखिम की घटना और व्यापकता, भोजन में संदूषण, खाद्य उत्पादों में विभिन्न संदूषकों के अवशेषों के संबंध में डाटा एकत्र करना और जोखिमों की पहचान करना है। वास्तव में इसका दायरा बहुत बड़ा है। सरकार समय–समय पर इसे और चुस्त दुरुस्त करने के लिए सहयोग करती रही है, लेकिन फिर भी यदा कदा मिलावट और अन्य तरह के आरोप लगते रहे हैं। एजेंसी कार्रवाई भी करती है लेकिन कई बार अदालतों ने प्रक्रियात्मक कमियों के कारण एजेंसी की कार्रवाइयों को खारिज कर दिया। जैसे कि वर्ष 2015 में न्यूट्रास्यूटिकल्स के मामले में।

एफएसएसएआई के पास 200 से अधिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, लेकिन लगातार बढ़ते उद्योग के आकार, इसमें शामिल खिलाड़ियों की संख्या और उनके द्वारा खेले जाने वाले क्षेत्रों और निर्यात बाजार के विस्तार को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त है। सरकार को और अधिक मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं बनाने, राज्य सरकार के स्तर पर कार्यशील खाद्य प्रयोगशालाएं सुनिश्चित करने और अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने तथा मानदंडों के कार्य को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मानकों को नियमित रूप से अधिकतम करने और इसे शक्ति से लागू करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे आने की जरूरत है। ❑❑

तपती धरती के लिए जिम्मेवार है इंसानी हरकतें

बेंगलुरु में पानी की किल्लत, ब्राजील की बाढ़, दुबई में बेतहाशा बारिश, उत्तराखंड में लगातार लहकते–जलते जंगल और भारत में विभिन्न इलाकों में हीट वेव की बढ़ती आक्रामकता से तपती धरती, चिंता का सबब बने हुए हैं। जलवायु बदलाव के ऐसे बहुपक्षीय दुष्परिणामों से दुनिया चिंतित है। इसे लेकर जहां–तहां बौद्धिक विमर्श तो आयोजित होते रहे हैं लेकिन समाधान के लिए जो ठोस पहल होनी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में जलवायु संकट को प्रमुखता से रेखांकित करेंगे लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के दस्तावेजों में यह मसला महज खाना पूर्ति की तरह एक कोने में दुबका हुआ है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार स्वाभाविक रूप से जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार से प्राप्त है। संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोगों के स्वच्छ हवा या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भारतीय न्याय शास्त्र में पहले से ही बहुतअच्छी तरह से मान्यता दी गई है और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती तबाही को देखते हुए इसके खिलाफ सुरक्षा का अधिकार बनाना आवश्यक था। क्योंकि प्रतिकूल प्रभाव अपने आप में विशिष्ट अधिकार है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से न केवल जलवायु परिवर्तन को लेकर आम जनता में जागरूकता बढ़ने की बात की गई बल्कि यह भी उम्मीद की गई कि लोग सरकार और संस्थाओं से इस मामले में जवाबदेह कार्यवाही की भी मांग करेंगे। आशा जगी कि सरकार और संस्थाएं ठोस पहल कर आम जन को राहत पहुंचाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगी।

देश का आम जन–जीवन जलवायु बदलाव से उत्पन्न होने वाले खतरों की हद में है। समय–समय पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल बदल रही है। पिघलते ग्लेशियर, चटखते हिमखंड और सर्दी गर्मी जैसे हर मौसम में पारा का थोड़ा और ऊपर उछल जाना, यह सब हमें उसी भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन न रह जाए।

पर्वत शिखरों में जमी बर्फ के पिघलने की रफ्तार अप्रत्याशित ढंग से बढ़ गई है। यह और न बढ़ने पाए इसके लिए अब तुरंत कदम उठाने का समय आ गया है।

–अनिल तिवारी

मालूम हो कि दुनिया के लगातार गर्म होते जाने की जानकारी कोई नई नहीं है। वर्ष 1824 में ही जोसेफ कोरियर ने बताया था की धरती पर यदि कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो धरती का तापमान बढ़ेगा। फलस्वरुप ध्रुवीय हिमखंड पिघल सकते हैं।लेकिन पिछले 200 वर्षों में हमने कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए कुछ नहीं किया। विकसित देशों ने तो घटाने की बजाय अपने बेतहाशा उपभोग के कारण इसे बढ़ाकर चरम पर पहुंचा दिया। एक अनुमान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान केवल कुछ गिने चुने विकसित देशों का ही है। इसके असली और सर्वाधिक गुनहगार वही है। ऐसे में गरीब और विकासशील देशों का मानना है कि इसको रोकने की शुरुआत विकसित देशों को ही करनी चाहिए। लेकिन लगे हाथ कुछ पर्यावरणविदों का यह भी कहना है कि विकसित देशों ने जिस जीवनशैली को अपना लिया है उसे रातों–रात छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है।

ऐसे में उन देशों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो तेजी से ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने वाली शैली को अपना रहे हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विकासशील अथवा अविकसित देश यह जोखिम ले सकते हैं कि वे ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अपनी विकास यात्रा को ही रोक दें।

आईपीसीसी जो विश्व के जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर में हो रहे शोधों का विश्लेषण कर बड़े निष्कर्ष प्रकाशित करती है के अनुसार 2023 का वर्ष पिछले लगभग एक लाख साल में सबसे गर्म बरस रहा। यहां तक की जून 2023 से पिछले मार्च 2024 तक लगातार 8 महीने में तापमान रिकार्ड स्तर पर बढ़ता रहा। विश्व का औसत तापमान इस दौरान सामान्य से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था जो बहुत ही असामान्य है। इस साल का मार्च वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म महीना था,औसत तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस था जो मार्च 2016 में पिछले उच्च तापमान से 0.16 डिग्री अधिक था। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर फसलों, पीने के पानी की उपलब्धता, बाढ़ और सुखा, भूस्खलन जैसी उग्र घटनाओं पर पड़ता है, वही निर्धन परिवारों की स्थिति और विकट हो जाती है। गर्मी के अधिक प्रकोप के समय भी खेत मजदूर, निर्माण मजदूर, सफाईकर्मी खुले में घंटे मेहनत करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि इसके बिना वे अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। किसान तो फिर भी अपने कार्य के समय को मौसम के अनुसार निर्धारित कर लेते हैं लेकिन दूसरों के यहां मजदूरी करने वालों को प्रायः उनकी बात माननी ही होती है। उनका अधिकांश कार्य विशेष कर मार्च से जून तक घोर गर्मी में ही होता है।

प्रश्न उठता है कि निरंतर गहराते पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? इसका सीधा उत्तर

है मनुष्य की अति भोग–बिलास वाली जीवन शैली।

इंसानी हरकतें कुदरत को रौद्र रूप दिखाने पर मजबूर कर रही है। वैसे तो चरम मौसमी घटनाओं का समूचा पैटर्न ही भयावह परिणाम दिखाने वाला है लेकिन जिस प्रकार से जैव विविधता पर असर पड़ रहा है और हमारे खान–पान की चीजों का स्वाद और उसके पोषक तत्वों में बदलाव आ रहा है, वह मानवीय अस्तित्व के लिए बड़े खतरे की तरह है।

इसमें कोई दो राय नहीं की मौसम के खेल से बेखबर हुकूमते पर्यावरण संरक्षण का काम सिर्फ कागजों में ही करती रही हैं। अब तो कागजों में भी महज खानापूर्ति है। भाजपा का घोषणापत्र मुख्य रूप से मौजूद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के बिस्तार पर केंद्रित है।कांग्रेस का घोषणा पत्र पर्यावरण मानको और जलवायु नीतियों को निर्धारित और लागू करने के लिए एक स्वतंत्र संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण बनाने की बात करता है। बीजेपी की नकल पर कांग्रेस ने भी 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्वरित कदम उठाने या कोई ठोस कार्रवाई किए जाने का वादा कहीं भी नहीं है। विडंबना पूर्ण है कि बेंगलुरु शहर पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रहा है, महीनों से उत्तराखंड के जंगलों में आग धधक रही है, बेमौसम बारिश, बाढ़, ओले जैसी कुदरती आपदाओं से जनजीवन बेहाल होता देखकर भी जवाबदेह संस्थाएं सुनने समझने को राजी नहीं है।

लेकिन अब हाथ पैर हाथ धर कर बैठने और एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय निकल चुका है। पर्वत शिखरों में जमी बर्फ के पिघलने की रफ्तार अप्रत्याशित ढंग से बढ़ गई है। यह और न बढ़ने पाए इसके लिए अब तुरंत कदम उठाने का समय आ गया है। हमारा पिछला रिकॉर्ड चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो लेकिन हम इसका कोई और समाधान अब भी निकाल सकते हैं बशर्ते सीमा, विश्व व्यापार, क्षेत्रीयता, पराए धन पर नजर गड़ाने एवं सभ्यताओं की जंग जैसे बेवजह के झगड़ों को ही सब कुछ मानकर हम इस चुनौती को ही ना भूल जाए। मानव सभ्यता और इस सुंदर सृष्टि को बचाना इस दशक का और इस सदी का सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जिस तरह भारतीय 'योग' को अपनाकर दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे हैं उसी तरह भारतीय जीवन शैली के 6 सूत्रों जिसमें त्याग के साथ उपभोग, अपने को सभी जीवो में देखना, एक सत्य का विविध रूपों में प्रकटीकरण, सभी सुखी रहें, वसुधैव कुटुंबकम् तथा पृथ्वी मेरी मां है एवं मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, शामिल है, को आत्मसात कर मानवता के समक्ष खड़े जलवायु बदलाव के बहुकोणीय संकटों से बचा जा सकता है। ❑❑

कब तक टिकेगा चुनावी रेवड़ियों का अर्थशास्त्र?

चुनाव के मौसम में वायदों और प्रलोभनों की भरमार है। कोई राजनीतिक दल कर्ज माफी और सबको लखपति बनाने की बात कर रहा है तो कोई मुफ्त लैपटॉप और महिलाओं को मुफ्त परिवहन के वायदे के साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है।

सत्ता पक्ष भी 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज जारी रखने और गरीबों को पक्का मकान, बिजली, गैस और स्वास्थ्य बीमा की दुहाई देकर वोट मांग रहा है।

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) की समीक्षा करने और 11.8 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मुफ्त खाद्यान्न सब्सिडी योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान भी इसी चुनाव को देख कर किया था। मुफ़्त की योजना और स्कीम लाने वाला कोई भी दल जनता को यह नहीं बताता कि ये वायदे कैसे पूरे होते हैं और इनका खर्च कौन उठाता है? जबकि सब जानते हैं कि पैसा अंततः करदाता की जेब से ही निकलता है।

कॉंग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी ने कहा है कि उनके सत्ता में आते ही देश से गरीबी भाग जायेगी, क्योंकि वह 30 करोड़ गरीबों को एक–एक लाख रुपये देने जा रहे हैं। राहुल गांधी का वादा शानदार है और लोग उन्हें 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनने की मांग कर रहे हैं। जाहिर है राहुल के पास इस बात का जवाब नहीं होगा कि कांग्रेस के 55 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन में रहने के बाद भी भारत क्यों एक अत्यंत गरीब देश बना रहा? फिर भी इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाता है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो सबको लखपति बनाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे? क्या देश के मिडिल क्लास से इसे वसूल करेंगे या कर्ज लेंगे? क्या एक जेब से दूसरे की जेब में पैसा डालने से गरीबी खत्म हो जाएगी? गरीबी हटाने के लिए किसी भी देश के पास कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल तेज विकास और भ्रष्टाचार खत्म कर के ही लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है।

भारत को अपने गरीब लोगों को सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि वे पैसा कमा सकें। उत्पादक रोजगार की उचित व्यवस्था ही गरीबी की समस्या को दूर कर सकती है, मुफ्त की चुनावी घोषणाएं नहीं।

–विक्रम उपाध्याय

राहुल गांधी ने कहा है कि वह हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये देंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से वह भारत से गरीबी को एक झटके में खत्म कर देंगे। दुनिया के तमाम बड़े अर्थशास्त्री यह कह चुके हैं कि मुफ्त पैसा देने से कभी भी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के लिए ही खतरनाक प्रयोग है। अगर सचमुच किसानों की कोई हालत सुधारना चाहता है तो बाजार तक फसलों के प्रवाह को सुनिश्चित करें ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। गावों में स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करे ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। गाँवों के पास अस्पताल बनाए ताकि इलाज के लिए शहर जाकर पैसा ना लुटाना पड़े। किसान भी मुफ्त का पैसा नहीं चाहते, वे वही चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं। मौजूदा मोदी सरकार 6,000 रुपये प्रति माह देकर किसानों की समस्या का समाधान होना मान रही है तो इसमे भी वोट हासिल करने की ही सोच है। जबकि अधिकतर किसानों को उत्पादन की वास्तविक लागत वापस नहीं मिलती है।

राहुल गांधी के मुताबिक उनकी क्रांतिकारी योजना के लागू होने के बाद भारत में कोई गरीबी नहीं बचेगी। फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि क्या अर्थव्यवस्था उसके बाद बच सकेगी? आखिर उनकी क्रांतिकारी योजनाओं की व्यवहारिकता कितनी है? क्या देश

के नौजवान सरकार पर निर्भर रह कर अपनी तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या किसान कर्ज और कर्जमाफी के चक्कर में फंसे रह कर किसानी को लाभप्रद बना सकते हैं? मजदूर सरकार से 6 हजार प्रति माह की दया पर जिंदा रह सकते हैं?

राहुल गांधी की योजना के अनुसार पैसा 12 हजार से कम कमाने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि परिवार को दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि परिवार का पुरुष सदस्य 6 हजार कमाता है और महिला सदस्य 6 हजार कमाती है, तो वह राहुल की स्कीम से बाहर है। राहुल गांधी के अनुसार 12 हजार रुपये महीने कमाने वाला एक संपन्न परिवार है। इसलिए वह इस स्कीम से बाहर रहेगा।

देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों में आने वाले अधिकांश लोग औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए उनकी आय भी स्थिर नहीं होती। फिर इस बात का हिसाब कोई कैसे रख सकेगा कि किसी मजदूर को वास्तव में कितना भुगतान मिला। किसी बेरोजगार को 72,000 सालाना भुगतान करके भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ऐसा दावा केवल चुनाव के समय ही किया जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि केवल इस बार ही मुफ्त योजनाओं की बाढ़ आई है। हाल के वर्षों में इस तरह की नीतियों की काफी चर्चा हुई है और विशेषज्ञों द्वारा चिंता भी जताई गई हैं। क्योंकि इस तरह के प्रलोभन का असर केंद्र और राज्य दोनों के राजकोष पर हुआ है। लोग इस बात के प्रति भी जागरूक हैं कि इन योजनाओं की भरपाई अंततः करदाता को ही करनी पड़ती है। हर तरह से करदाता पिसता है। एक तरफ उच्च करों के रूप में वह भुगतान करता है, और दूसरी तरफ महंगाई भी झेलता है। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चेताया है कि कई राज्य

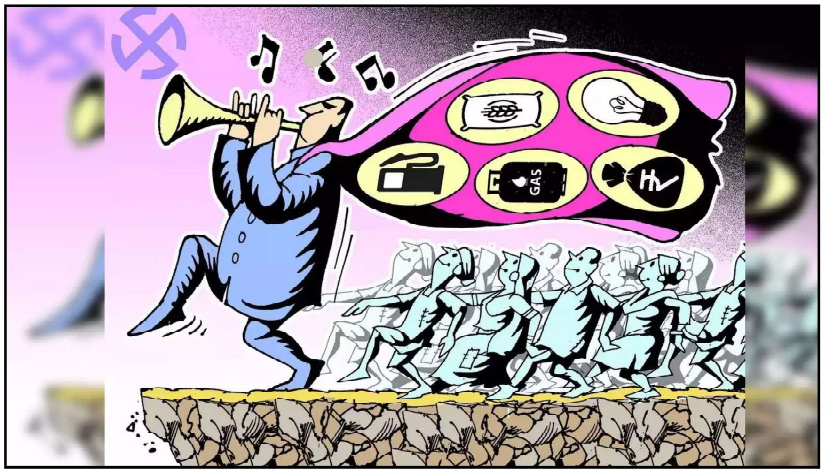

बिना वित्तीय व्यवहारिकता को ध्यान में रखे मुफ्त सुविधाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जब धन आवंटन की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुफ्तखोरी संस्कृति पर प्रहार करते हुए श्रीलंका के ऋण संकट का उदाहरण दे चुके हैं।

कर्नाटक बजट पर एसबीआई इकोरैप ने भी कहा है कि सरकार को पांच चुनाव पूर्व गारंटी को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 60,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। खुद सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को करदाताओं के खर्च पर नकदी और अन्य मुफ्त चीजें बांटने पर चिंता जता चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक का भी कहना है कि गैर जरूरी सब्सिडी पर व्यय बढ़ने से पूंजीगत व्यय के लिए पूंजी बाधित हो सकती है।

कई राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 8–9 प्रतिशत सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं। बिजली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय कम करते जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी है। केवल इस कदम से उनका पेंशन पर राजकोषीय बोझ 4 से 5 गुना तक अधिक बढ़ गया है।

अब बात करते हैं मुफ़्त की योजनाओं की अर्थव्यवस्था की। प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपये, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने से बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारा बजट घाटा चिंताजनक तरीके से नहीं बढ़ेगा और उसके कारण बुनियादी ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भरपूर पैसा उपलब्ध होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए जरूरी बजट का आवंटन होगा? क्या इससे भारत की संभावित आर्थिक वृद्धि पर असर नहीं पड़ेगा? एक आकलन के अनुसार राहुल गांधी की स्कीम वास्तव में लागू करने के लिए लगभग 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी।

पूरी दुनिया में यह तथ्य मान्य है कि मुफ्त नकदी के उपहार से महंगाई बढ़ती है। जिन देशों ने कोविड के दौरान लोगों को नकद पैसे दिए, वहाँ उसी अनुपात में मुद्रास्फीति भी बढ़ी। मुफ्त सुविधाएं गरीबों के एक बड़े वर्ग को गरीब बने रहने के लिए मजबूर करेगी। भारत को अपने गरीब लोगों को सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि वे पैसा कमा सकें। उत्पादक रोजगार की उचित व्यवस्था ही गरीबी की समस्या को दूर कर सकती है, मुफ्त की चुनावी घोषणाएं नहीं। ❑❑

खटाखट योजनाओं का नुकसान

पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला है, जिसमें वह कहते हैं कि उनकी सरकार केंद्र की कुर्सी पर जैसे ही काबिज होगी, उसी दिन से हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में हर महीने साढ़े आठ हजार रुपए मिलने वाले हैं, खटाखट–खटाखट, खटाखट– खटाखट। वीडियो में आखिरी खटाखट के बाद चेकों की बरसात दिखाई जाती है ताकि नासमझ लोग भी समझ जाए कि गरीबों को किस गति से और कितना पैसा देने वाले हैं कांग्रेस के कथित शहजादे। एक अन्य वीडियो में राहुल गांधी वादा करते हैं कि सरकार बनते ही देश में वे करोड़ों लखपति पैदा करने वाले हैं।

यह तो रही कांग्रेस के भविष्य और पार्टी के एक तरह से सर्वे–सर्वा राहुल गांधी यानी कथित शहजादे की बात। दूसरी तरफ वाले साहब भी कम नहीं है। 84 करोड लोगों को अगले 5 साल तक 5 किलो मुफ्त राशन के साथ–साथ सार्वजनिक मंचों से लगातार लखपति दीदियों की पूरी की पूरी फौज तैयार करने का वायदा करते आ रहे हैं। मोटे तौर पर चुनावी सभाओं में साहब कांग्रेस और मुसलमान पर उल्टे सीधे आरोप नहीं लग रहे होते हैं तो सच मानिए दिल खोलकर वादे लूटाने में लगे रहते हैं। वे डंके की चोट पर कहते हैं कि तीसरी बार जीतने के बाद जनता के लिए एक से बढ़कर एक अनोखी अद्भुत लाभकारी योजनाएं लेकर आएंगे। वे लगातार याद भी दिला रहे हैं कि पिछले 10 सालों से यथासंभव गैस के चूल्हे, पीने का पानी, शौचालयों के लिए पैसे, आयुष्मान कार्ड और मुफ्त राशन तो पहले से ही दे रहे हैं, आगे इसकी फेहरिस्त और लंबी होने वाली है। देश की 140 करोड़ जनता को अपना वारिस बताने वाले साहब की शर्त बस इतनी है की तीसरी बार भी जनता उन्हें चुनकर दिल्ली भेज दे। तीसरी बार 400 के पार का तोहफा उन्हें दे दे। इस चुनाव का यही वह दिलचस्प पहलू है जहां सभी राजनेताओं ने मतदाताओं का साधारणीकरण करते हुए उनके वोट के बदले में उन्हें आधिकाधिक खैरात दिए जाने का वचन दिया है।

देश की जनता को तय करना है कि वह श्रम और रोजगार के विस्तार से विकसित होने का सपना देखना चाहती है अथवा मुफ्त का माल हजम कर जैसे तैसे दिन काटने की आदत को बढ़ावा देती है।

–शिवनंदन लाल

पर सवाल यह है कि समाज कल्याण की आड़ में दोनों हाथ से लूटाने का वादा करने वाले साहब या शहजादे इसके लिए भारी भरकम राशि कहां से लाएंगे। देने के दावे तो इस अंदाज में किये जा रहे हैं जैसे सारा का सारा माल इनका निजी धन हो। अगर नहीं तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद वादा पूरा करने के क्रम में यह राशि देश के खाते कमाते लोगों से वसूली जाएगी। उन पर कई तरह के अतिरिक्त कर थोपे जाएंगे।

देश की आम जनता पहले से ही त्रस्त है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया का मूल्य लगातार गिर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र खस्ताहाल हैं। लोकतांत्रिक इकाइयां लगभग ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में देश की जनता को उम्मीद थी की 18वीं लोकसभा के लिए मैदान में उतरे कम से कम बड़े राजनीतिक दल आम जनता की बेहतरी के लिए कुछ बड़े और अच्छे परिणामदायी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे तथा देश के चतुर्दिक विकास के लिए अपना एजेंडा रखेंगे। चुनाव प्रारंभ होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत बनाने पर खास फोकस कर रहे थे। भारत के जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तथा आजादी के 100 साल पूरा होने पर दुनिया में अव्वल बनाने का दावा कर रहे थे। लेकिन अब जैसे–जैसे चुनाव अपने आखिरी

पड़ाव की ओर बढ़ रहा है वैसे–वैसे प्राथमिकताएं भी बदलती जा रही हैं। अधिक से अधिक मतदाताओं को लुभाने के लिए खैरात का पिटारा तो खुल ही चुका है, दिन प्रतिदिन भाषा भी सतही हो चली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खटाखट खटाखट को अब मोदी ने अपने हर भाषणों में तकिया कलाम बना लिया है। प्रधानमंत्री के तंज की एक बानगी देखिए, "चार जून के बाद इंडि गठबंधन विदेश में आराम फरमाने निकल लेगा "खटाखट खटाखट"। विपक्षी दल के नेता भी पीछे नहीं है। सपा के अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के खटाखट का जवाब फटाफट, गटागट और सटासट की अर्धाली मिलाकर दे रहे हैं।

मामला सब धान बाईस पसेरी वाला हो गया है। कांग्रेस पार्टी पहले संविधान को खतरे में बता कर सत्तापरिवर्तन के लिए समान विचार वाले दलों का गठबंधन तैयार कर नीतियों के आधार पर बदलाव की बात कर रही थी। वही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी दल भव्य विरासत को रेखांकित करते हुए विकसित भारत का दावा कर रहा था। लेकिन आधा चुनाव बीतते बीतते दोनों पक्ष एक ही धरातल पर आ खड़ा हुआ है।

अब दोनों ओर से ताल ठोककर कहा जा रहा है कि जनता हमारे दल को जिताएगी तो हम जनता को बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य आवास अनाज सब कुछ मुफ्त में मुहैया कराएंगे। भाजपानीत एनडीए की सरकार ने अगले 5 साल तक 5 किलो मुफ्त राशन का वादा किया है तो अब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने पर 10 किलो मुफ्त राशन का लॉलीपॉप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की लखपति दीदी योजना का नकल करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में करोड़ों लखपति पैदा करने का दावा किया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से

किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास पर निर्भर करता है। जिन देशों के लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वहां की सरकारें भी उसी अनुपात में देश को आगे ले जाने का काम करती है।

जनता को अपने पाले में करने के लिए ऑफर दर ऑफर पेश किया जा रहे हैं। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन नेतागण चुनाव में अपनी नीतियों के आधार पर समर्थन मांगने की जगह मतदाताओं के हाथ में भीख का कटोरा थमा रहे हैं। कोई कटोरे में 10 रू. डालने को कह रहा है तो कोई कह रहा है कि अगर हमें जीताओगे तो हम 100 रू. डालेंगे। कोई 5 किलो राशन दे रहा है तो कोई 5 किलो को बहुत कम बताकर 10 किलो देने का दावा कर रहा है।

किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास पर निर्भर करता है। जिन देशों के लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वहां की सरकारें भी उसी अनुपात में देश को आगे ले जाने का काम करती है। ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है जहां जनता को कमजोर करके देश को मजबूती प्रदान की गई हो। हमारे देश में सब कुछ मुफ्त में देने की आदत डाली जा रही है। कल्याणकारी राज्य बताकर समाजवादी आर्थिक नीतियों के नाम पर हमारा शासक वर्ग सेंत मेंत में चीजों को मुहैया कराने का हिमायती रहा है। जनता में पहले यह विश्वास पैदा किया गया कि सब कुछ सरकार ही देती है यहां तक की रोजी रोजगार भी।

उदारीकरण के बाद स्थितियां थोड़ी बदली। आम आदमी सरकार के भरोसे कम,अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ाने की दौड़ में शामिल हुआ। कोटा परमिट का राज खत्म होने के बाद विकास ने रफ्तार पकड़ी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। भूमंडलीकरण के बाद भारतीय मेधा का पूरी दुनिया में डंका बजने लगा। विशेष रूप से आईटी के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की।

लेकिन वर्तमान चुनाव में जो बातें पक्ष और विपक्ष द्वारा उठाई जा रही हैं, जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं उनसे अच्छे भविष्य के संकेत नहीं मिलते। एक दल कह रहा है कि अगर वह चुनकर आए तो संविधान को मिटा देंगे तो दूसरा कह रहा है कि अगर वह चुने गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। एक तरफ से कहा जा रहा है कि वोट के लालच में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है तो दूसरे का आरोप है की चुनाव जीतने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन जब मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात आती है तो दोनों ही दल खटाखट सामान कगूरे पर खड़ा होकर फटाफट अधिक से अधिक देने का दावा करने लगते हैं। अब तक जनता को मिलने वाले लाभों को गटागट डकार जाने वाले भी चुनाव जीतने पर अधिक से अधिक सुविधाएं सटासट उड़ेल देने की बात कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि राजनेता देश की अधिकांश जनता को मुफ्त के जाल में फंसाकर सदैव के लिए परजीवी बना कर रखना चाहते हैं ताकि हर मौके पर उनकी 'पौ बारह रहे'। ऐसे में देश की जनता को तय करना है कि वह श्रम और रोजगार के विस्तार से विकसित होने का सपना देखना चाहती है अथवा मुफ्त का माल हजम कर जैसे तैसे दिन काटने की आदत को बढ़ावा देती है। ❑❑

जीएमओः जैव- साम्राज्यवाद

पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के देशों में जीएमओ फसलों को खाद्य सुरक्षा और कुपोषण संकट के समाधान के रूप में प्रचारित किया गया है। हालांकि भूख, बीमारी और कुपोषण में वृद्धि हुई है जबकि जैव विविधता में गिरावट आई है और विषाक्त पदार्थ चारों तरफ फैल गए हैं। जीएमओ साम्राज्यवाद में छोटे किसानों के जीवन और आजीविका तथा उत्पत्ति के केदो में जैव विविधता को नष्ट कर दिया है। जैव विविधता के यह केंद्र दुनिया की खाद्य आपूर्ति, बीमारी, जलवायु चुनौतियां, प्राकृतिक आपदाओं या खाद्य उत्पादन में अन्य बाधाओ से सुरक्षा के उद्‌गम स्थल है।

मेक्सिको दुनिया का एक बड़ा मकई (मक्का) उत्पादक देश है। जीएमओ साम्राज्यवाद ने वहां की जैव विविधता को नष्ट करने का प्रयास किया। वहां के निवासियों का जीवन निर्वाह और कृषि संस्कृति एक तरह से खतरे में पड़ गई। लेकिन जीएमओ साम्राज्यवाद की कारस्तानी समझ में आने के बाद वहां के समाज और संगठित समुदायों द्वारा एक लंबा संघर्ष किया गया। इस संघर्ष के बाद ही मैक्सिकन समाज ने बार मॉनसूंटो सिजेंटा और कटेवा एग्री साइंस कंपनियों के खिलाफ ले गए एक सामूहिक मुकदमे के माध्यम से आनुवंशिक रूप से संशोधित मकई के रोपण पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध अभी भी प्रभावित है। अभी हाल ही में मैक्सिकन सरकार ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर ग्लाइकोसाइड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया और वहां के मुख्य भोजन टॉर्टिला में आनुवांशिक रूप से संशोधित मकई के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय का विरोध करते हुए अमेरिकी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुक्त व्यापार समझौते के आधार पर आदेश को रद्द करने और देश में जीएमओं की शुरुआत को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से विवाद समाधान तंत्र को एक बार फिर सक्रिय किया है। मैक्सिकन सरकार के साथ–साथ मेक्सिको के गैर सरकारी संगठनों ने भी विस्तृत वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इस पैनल के समक्ष अपनी तकनीकी राय प्रस्तुत की, जिसमें मेक्सिको के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा कुछ नए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, जो वहां के शैक्षणिक संस्थाओं के सुस्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित

अब समय आ गया है कि खाद्य प्रणालियों को कारपोरेट कंपनियों को थोपे जाने के मामले को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मेक्सिको की लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता बनाते हुए समर्थन दिया जाए तथा संघर्ष को मजबूती प्रदान किया जाए।

– डॉ. वंदना शिवा

थे। इन साक्ष्यों ने उनके युग्मन के बारे में बताया और चेतावनी दी है जो मैक्सिकन आबादी के भोजन में और अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में आनुवांशिक रूप से हेर फेर किए गए मक्के की उपस्थिति को रोकने के लिए प्रासंगिक और जरूरी बनाते हैं।

गत 12 से 16 मार्च 2024 तक नवदान्य इंटरनेशनल ने लैटिन अमेरिकी साझेदारों और मैक्सिकन सरकार के साथ मिलकर नए और पुराने जीएमओ को थोपने के खिलाफ एक आम रणनीति बनाने के लिए मैक्सिको सिटी में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। मेक्सिको सिटी में हुई लामबंदी मैक्सिकन नागरिक समाज संगठनों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण और प्राकृतिक मंत्रालय के सहयोग से अर्जेंटीना, कोलंबिया, बोलिविया, कोस्टारिका और अन्य लैटिन अमेरिकी आंदोलन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर आधारित थी। मेक्सिको की जैव विविधता वाली पारंपरिक कृषि प्रणाली को वहां के संसाधन और संस्कृति मंत्रालय ने भी सुरक्षा संरक्षा दिए जाने की बात की।

मेक्सिको कि यह घटना वहां के लोगों की अपनी जैव विविधता संस्कृतियों, उनकी हजार साल पुरानी खाद्य विरासत, उनकी आबादी के स्वास्थ्य और परिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। यह उन लोगों का मामला है जो अपनी संप्रभुता के लिए सम्मान की मांग करते हैं और उन स्थानों के लिए आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां जीएमओ साम्राज्यवाद थोपने की तैयारी हो रही है। गौरतलब है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर संप्रभुता रखने का अधिकार है और इसकी शुरुआत खाद्य संप्रभुता से होती है।

हालांकि जीएमओ का एजेंडा हमेशा पेटेंट और मुनाफे के बारे में रहा है, भोजन और स्वास्थ्य के बारे में कभी

आज हमारी बीज संप्रभुता को बौद्धिक संपदा अधिकारों और नई जीएमओ प्रौद्योगिकियों से खतरा है, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कृषि खाद्य कंपनियों के नियंत्रण और एकाधिकार के तहत बीजों को एक सामान्य वस्तु से एक विशेष वस्तु में बदल दिया है।

नहीं। खाद्य संप्रभुता एक उच्च स्तरीय अवधारणा है क्योंकि इसका तात्पर्य प्राणियों की खुद को प्रबंधन और व्यवस्थित करने और स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करने की संप्रभुता से है। यही कारण है कि औद्योगिक कृषि का लक्ष्य सदैव किसानों को भूमि से दूर धकेलता रहा है या औद्योगिक कृषि की परिभाषा में ही अंतरनिहित है, एग्रो टैक्सन जीएमओ और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को थोपने, विविधता और प्राचीन खाद्य संस्कृतियों को नष्ट करने और भूमि पानी और जैव विविधता को खतरे में डालने से लोगों किसानों और प्रकृति की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है।

कृषि व्यवसाय और जैव प्रौद्योगिकी दिग्गज एनबीटी (नई प्रजनन तकनीक) जैसे नए संक्षिप्त शब्दों के तहत जीएमओ को बढ़ावा देने के लिए जीमोओ नियमों में सूक्ष्म परिवर्तन करके मौजूद जैव सुरक्षा नियमों जैसे की जैविक विविधता पर कन्वेंशन के कारटाजेना और नागोया प्रोटोकॉल को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। एनजीटी (नई जिनोमिक तकनीक) या टीईए (सहायक विकास की तकनीक)।

इतना ही नहीं रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी के दिग्गजों के हाथों में पेटेंट एकाधिकार बनाए रखने के उद्देश्य से इन नए जीएमओ को विभिन्न देशों में लागू कृषि कानून में चुपके से शामिल किया गया है अथवा शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

आज हमारी बीज संप्रभुता को बौद्धिक संपदा अधिकारों और नई जीएमओ प्रौद्योगिकियों से खतरा है, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कृषि खाद्य कंपनियों के नियंत्रण और एकाधिकार के तहत बीजों को एक सामान्य वस्तु से एक विशेष वस्तु में बदल दिया है। कॉरपोरेट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों और प्रकृति की संप्रभुता और अधिकारों का उल्लंघन करते हुए इसका लगातार थोपा जाना जारी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे जैव विविधता को चुराकर अमीर बन जाती है। ऐसे में बेश्विक नागरिक के रूप में हमें जीएमओ की बदमाशी का विरोध करने और अपने बीजों की रक्षा करने के लिए एक जुट होना ही चाहिए। आज दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी सरकार द्वारा जीएमओ के अवैज्ञानिक, अलोकतांत्रिक और पारिस्थितिकी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नागरिक उठ रहे हैं। नागरिकों के विरोध के कारण जीएमओ की पहली पीढ़ी असफल रही है लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अधिक चतुराई करते हुए विविधता के केदो में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवो या नए जीएमओ को थोपना चाहती हैं। यह कंपनियां प्रकृति और जैव विविधता को व्यवसायीकरण और एकाधिकार की वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में पूरे मामले को अंधेरे में रखकर हेर फेर करने में लगी है। ऐसे में अब समय आ गया है कि खाद्य प्रणालियों को कारपोरेट कंपनियों को थोपे जाने के मामले को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मेक्सिको की लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता बनाते हुए समर्थन दिया जाए तथा संघर्ष को मजबूती प्रदान किया जाए। ❑❑

स्थिर और मजबूत रुपये की आहट

कई दशकों की लगातार गिरावट के बाद, वर्ष 2023–24 में रुपया स्थिर होने लगा है, खासकर इसकी तीसरी और चौथी तिमाही में। हम कह सकते हैं कि वर्ष 2023–24 भारतीय रुपये के लिए बहुत शुभ रहा। गौरतलब है कि वर्ष 2023–24 की पहली दो तिमाहियों में रुपये में डॉलर के मुकाबले मात्र 1.0 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों में रुपया–डॉलर विनिमय दर 83.0 रुपये प्रति डॉलर के आसपास स्थिर हो गई। इस प्रकार की स्थिति आमतौर पर अतीत में नहीं देखी गयी है।

हम देखते हैं कि 1980 के दशक से ही रुपये का मूल्य लगातार गिरता रहा है, जब हमारा देश प्रशासित विनिमय दर की व्यवस्था से हटकर बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर आ गया था। यह उल्लेखनीय है कि रुपया–डॉलर विनिमय दर 1982 में 9.46 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2023 में 82.17 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर हो गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि 1982 से लेकर मार्च 2023 तक डॉलर में 868.6 प्रतिशत की गिरावट आई है, यानि पिछले 41 सालों में 5.41 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रूपए का अवमूल्यन हुआ है। ऐसा देश में तेजी से बढ़ते आयातों और उससे कहीं कम गति से बढ़ते निर्यातों के कारण हुआ है।

घटता चालू खाता घाटा

पिछले एक साल में, हम माल और सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। चालू खाते पर घाटा वर्ष 2023–24 की पहली तीन तिमाहियों में घटकर केवल 28 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत है। चौथी तिमाही के पहले दो महीनों में घाटा अधिशेष में बदल गया है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है, तो पूरे वर्ष के लिए चालू खाते पर घाटा लगभग 30 अरब अमरीकी डॉलर तक कम हो सकता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम हो सकता है, जो वर्ष 2022–23 के चालू खाते पर घाटे (66 बिलियन अमरीकी डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत), से बहुत कम है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तीन तिमाहियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों से आने वाले प्रेषण में वृद्धि से इसकी भरपाई हो रही है। इसी प्रकार, अमेरिका और यूरोप में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद, भारतीय मूल के लोगों से आने वाले धन में वृद्धि जारी रही और 2022–23 में 125 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2023–24 में इसके 135 अरब अमरीकी डॉलर होने की संभावना है।

अधिकांश देश धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से डॉलर व्यापार से दूर जा रहे हैं। इसके बजाय, वे व्यापार का निपटान अपनी मुद्राओं में करना चाहते हैं।
– स्वदेशी संवाद

डॉलर की बढ़ रही हैं मुश्किलें

प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही हम डॉलर के मूल्य में निरंतर वृद्धि देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने आपूर्ति के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका को सोने में भुगतान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बन गया।

युद्ध की समाप्ति के बाद विभिन्न देशों ने अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया और इसके साथ ही दुनिया में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' समाप्त हो गया और इस प्रकार डॉलर दुनिया की सबसे पसंदीदा मुद्रा बन गई। सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का अधिक से अधिक हिस्सा डॉलर के रूप में रखने लगे। लेकिन वर्ष 2000 के बाद अंतरराष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर का महत्व कम होता गया और अब यह लगभग 58 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

इतिहास में दुनिया भर के देशों के डॉलर के प्रति आकर्षण के कारण, डॉलर दुनिया की अन्य मुद्राओं, विशेष रूप से विकासशील देशों की मुद्राओं के मुकाबले लगातार मजबूत होता गया। भारत में जहां 1964 में एक डॉलर केवल 4.66 रुपये के बराबर था और अब यह लगभग 83.38 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। शायद इसीलिए दुनिया के सभी देश डॉलर को आरक्षित मुद्रा के रूप में रखने और अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान केवल डॉलर में करने में रुचि रखते हैं। डॉलर की इस बढ़ती मांग के कारण, डॉलर साल दर साल मजबूत होता रहा। हालांकि वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व कैरेंसी के रूप में अमरीकी डॉलर का हिस्सा 70 प्रतिशत से घटता हुआ अभी तक मात्र 58 प्रतिशत ही रह गया है, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व का दावा है कि अमेरिकी डॉलर वैश्विक स्तर पर सबसे पसंदीदा मुद्रा बनी हुई है, लेकिन समझना होगा कि डॉलर की लोकप्रियता में गिरावट निरंतर जारी है।

विडॉलरीकरण का स्पष्ट संकेत

हम देखते हैं कि अधिकांश देश धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से डॉलर व्यापार से दूर जा रहे हैं। इसके बजाय, वे व्यापार का निपटान अपनी मुद्राओं में करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत पहली बार व्यापार निपटान के लिए रुपया–व्यापार तंत्र को बढ़ावा दे रहा है; और लगभग 20 देशों ने, जिनमें अन्य देशों के अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कुबेत, ओमान, कतर भी शामिल हैं, इसके लिए सहमति व्यक्त की है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए वास्ट्रो खाते खोले हैं। चीन भी युआन में व्यापार निपटान के लिए जोर दे रहा है। ये वैकल्पिक व्यापार निपटान तंत्र धीरे–धीरे गति पकड़ रहे हैं। हालाँकि, डॉलर का हिस्सा अभी भी लगभग 58 प्रतिशत है, फिर भी यह बदलाव स्पष्ट और ध्यान देने योग्य है।

अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व और व्यापार के निपटान के लिए बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर रखने की मजबूरी, सामान्य रूप से दुनिया और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए यह बहुत शुभ नहीं रही है। डॉलर का वैश्विक रिजर्व कैरेंसी के रूप में प्रभुत्व विकासशील देशों के लिए शुभ नहीं रहा है। एक तरफ अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता और दूसरी तरफ उसके बावजूद डॉलरों के भंडार को रखने की मजबूरी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में रूस–यूक्रेन संघर्ष और दुनिया में अन्य प्रकार से अशांति और बाधाओं के कारण से कुछ विकासशील देशों और क्षेत्रीय ब्लॉकों द्वारा घरेलू मुद्राओं में व्यापार करने के प्रयासों को मदद मिली है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हुई है। इसने अमेरिकी वैश्विक वित्तीय आधिपत्य के लिए एक बड़ा झटका दिया है। कच्चे तेल के आयात में अमेरिकी डॉलर की अनिवार्यता की समाप्ति, गैर–डॉलरीकरण और अंतर–देशीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि की दिशा में चल रहे वैश्विक रुझान को दर्शाती है। सबसे पहले, रूस से कच्चे तेल की बड़ी खरीद और रुपये और गैर–डॉलर मूल्यवर्ग के भुगतान करना, भारत–यूएई द्वारा भारतीय रुपये में समझौता, दक्षिणी विश्व के देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने से विकासशील देशों को बड़े लाभ हुए हैं, जिसमें विनिमय दरों में कमी और अमेरिकी डॉलर से जुड़ी अस्थिरता को कम करके व्यापार को अधिक पूर्वानुमानित और स्थिर बनाना शामिल है।

आत्मनिर्भर औद्योगिक नीति का भी मिल रहा लाभ

गौरतलब है कि पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से देश में आयात तेजी से बढ़े हैं, जबकि निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। देश में बढ़ती आमदनियों और औद्योगिक विकास के अभाव में देश में आयात लगातार बढ़ते गए और निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, यह देश में रूपए के अवमूल्यन का एक बड़ा कारण बना। लेकिन वर्ष 2021 में कोरोना महामारी से सीख लेते हुए भारत ने तेजी से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना शुरू किया है। पीएलआई यानि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से अब उन सब उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा, जो गैरबराबरी की विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के कारण बंद हो गए थे। इसके साथ ही साथ नई पीढ़ी के उद्योगों जैसे सोलर विद्युत उपकरण, सेमी कंडक्टर, टेलीकॉम और ड्रोन इत्यादि को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास चल रहा है। इन सब प्रयासों के मद्देनजर सरकार द्वारा प्रोत्साहित सभी क्षेत्रों में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। इन सब के कारण जहां एक ओर आयातों पर अंकुश लगेगा, निर्यातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत का व्यापार घाटा और भुगतान शेष घाटा दोनों कम होंगे। इसके कुछ चिन्ह पिछले एक वर्ष में मिलना शुरू हुए हैं, और इस प्रवृत्ति की और अधिक बढ़ने की आशा है। ❑❑

आर्थिक क्षेत्र में नित नए विश्व रिकार्ड बनाता भारत

दिनांक 1 मई 2024 को अप्रेल 2024 माह में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण से सम्बंधित जानकारी जारी की गई है। हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि माह अप्रेल 2024 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो निश्चित ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 में वस्तु एवं सेवा कर का औसत कुल मासिक संग्रहण 1.20 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया एवं वित्तीय वर्ष 2024 में 1.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। अब तो अप्रेल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के स्तर से भी आगे निकल गया है। इससे यह आभास हो रहा है कि देश के नागरिकों में आर्थिक नियमों के अनुपालन के प्रति रुचि बढ़ी है, देश में अर्थव्यवस्था का तेजी से औपचारीकरण हो रहा है एवं भारत में आर्थिक विकास की दर तेज गति से आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले 2/3 वर्षों में 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत में वर्ष 2014 के पूर्व एक ऐसा समय था जब केंद्रीय नेतृत्व में नीतिगत फैसले लेने में भारी हिचकिचाहट रहती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की हिचकोले खाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। परंतु, केवल 10 वर्ष पश्चात केंद्र में मजबूत नेतृत्व एवं मजबूत लोकतंत्र के चलते आज वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।

भारत आर्थिक क्षेत्र में आज पूरे विश्व में एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है एवं अपनी विकास दर को 10 प्रतिशत के ऊपर ले जाने का भरसक प्रयास कर रहा है। इससे निश्चित ही भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

–प्रहलाद सबनानी

आज भारत आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर नित नए रिकार्ड बना रहा है। वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रेषण के मामले में आज भारत प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। भारत में आज सबसे बड़ा सिंक्रोनाईजड बिजली ग्रिड है। बैकिंग क्षेत्र में वास्तविक समय लेनदेन की सबसे बड़ी संख्या आज भारत में ही सम्पन्न हो रही है। भारत आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है एवं भारत आज पूरे विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। भारत में आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेट्वर्क है। मात्रा की दृष्टि से भारत में आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मासीयूटिकल उद्योग है। भारत में आज पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क है। भारत ने स्टार्टअप को विकसित करने के उद्देश्य से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा कर लिया है। भारत का स्टॉक बाजार, पूंजीकरण के मामले में, विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेट्वर्क है। विश्व में पैटेंट हेतु आवेदन किए जाने वाले देशों में भारत आज छठे स्थान पर आ गया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत को यह सभी उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राप्त हुई हैं।

पिछले केवल 10 वर्षों के दौरान शेयर बाजार में निवेशकों को अपार सफलता हासिल

हुई है और सेन्सेक्स ने 200 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है, इसी प्रकार निफ्टी भी इसी अवधि में 206 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा है। यह स्थानीय एवं विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना विश्वास जता रहा है। भारत में शेयर बाजार में व्यवहार करने के उद्देश्य से खोले जाने वाले डीमेट खातों की संख्या वर्ष 2014 में 2.2 करोड़ थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 15.13 करोड़ हो गई है अर्थात इन 10 वर्षों में 7 गुणा से अधिक की वृद्धि दर अर्जित की गई है। देश का प्रत्येक उद्यमी, उपक्रमी, व्यवसायी बहुत उत्साह में है कि देश में व्यापार करने हेतु वातावरण में बहुत सुधार हुआ है एवं ईज आफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार हुआ है। आज भारत ही नहीं बल्कि भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में भी पूंजी उगाहना बहुत आसान हो गया है। अतः एक प्रकार से उद्यमियों के लिए पूंजी की समस्या तो नहीं के बराबर रह गई है।

भारतीय नागरिकों में आज स्व का भाव जगाने में भी कामयाबी मिली है, जिसके चलते स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग बढ़ रहा है एवं अन्य देशों से विभिन्न उत्पादों के आयात कम हो रहे हैं। इसके चलते भारत के विदेशी व्यापार घाटे में सुधार दृष्टिगोचर है। आज भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में मामूली वृद्धि दर्ज हो रही है तो कई उत्पादों के आयात में कमी दिखाई देने लगी है। इसे भारतीय नागरिकों के आत्म निर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा सकता है। फरवरी 2024 माह में भारत का व्यापारिक निर्यात 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 4140 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया, जो पिछले 20 महीनों में उच्चतम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त, सेवा निर्यात 3210 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फरवरी 2024 माह में माल एवं सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 7355 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है, जो फरवर 2023 की तुलना में 14.2 प्रतिशत अधिक है। इसी कारण से, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज 64,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है।

आज भारतीय नागरिकों ने सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हुए भारत को विकसित एवं मजबूत बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। आज भारत में प्रत्येक नागरिक का औसत जीवन वर्ष 2022 के 62.7 वर्ष से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गया है। यह भारत में लगातार हो रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते ही सम्भव हो सका है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में पिछले 12 महीनों के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृद्ध दर्ज हुई है। इसी प्रकार, एक सर्वे के अनुसार, आज भारत में 36 प्रतिशत कम्पनियां आगामी 3 माह में नई भर्तियां करने पर गम्भीरता से विचार कर रही हैं, इससे भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं।

गरीब वर्ग को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाये जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन ने पूरे भारत में 75 प्रतिशत से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करके एक बढ़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। लगभग 4 वर्षों के भीतर मिशन ने 2019 में ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को 3. 23 करोड़ घरों से बढ़ाकर 14.50 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी प्रकार, पीएम आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश भर में 2.8 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। विश्व भर के सबसे बड़े सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – के अंतर्गत 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल एवं अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज के मासिक वितरण से 80 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है। पीएम उज्जवल योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किये गए हैं। इन महिलाओं के जीवन में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है क्योंकि ये महिलाएं इसके पूर्व लकड़ी जलाकर अपने घरों में भोजन सामग्री का निर्माण कर पाती थीं और अपनी आंखों को खराब होते हुए देखती थीं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को कायम रखा जा सका है। जन धन खाता योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक खाते खोलकर नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इससे गरीब वर्ग के नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। पूरे भारत में 11,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो 50–90 प्रतिशत रियायती दरों पर आवश्यक दवाएं प्रदान कर रहे हैं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में आज पूरे विश्व में एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है एवं अपनी विकास दर को 10 प्रतिशत के ऊपर ले जाने के भरसक प्रयास कर रहा है। इससे निश्चित ही भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं इसके बाद वर्ष 2027 तक भारत एक विकसित राष्ट्र भी बन जाएगा। ❑❑

किसानों पर शिकंजे जैसा है 'फ्री ट्रेड' फार्मूला

मुक्त व्यापार कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा। पहले की 'फेयर एंड लवली' क्रीम, जिसे अब 'ग्लो एंड लवली' नाम दिया गया है, की तरह फ्री ट्रेड दुनियाभर के बड़े कारोबारों को आसानी से आकर्षित कर सकता है ताकि ग्लोबल साउथ के देशों यानी गरीब व विकासशील देशों को इसकी विशाल आर्थिक क्षमता पर विश्वास हो सके। विवादास्पद 'फेयर एंड लवली' क्रीम ने भी त्वचा को कथित गोरा करने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद के साथ ऐसा ही किया। 'गोरे' को सुंदर और 'सांवले' को बदसूरत समझना सांवली त्वचा वाले लोगों का उपहास करने जैसा था और अंततः कंपनी को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा।

मुक्त व्यापार को लेकर दबाव का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस साल की शुरुआत में यूरोप में विशाल किसान आंदोलन हुए। 27 यूरोपीय देशों में से 24 किसी न किसी स्तर पर विरोधों का सामना कर रहे हैं। इन आंदोलनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) को 'उखाड़ फेंकने' का आह्वान कर रहे थे जिसकी वजह से यूरोप में भोजन व फल–सब्जियां सस्ते हो गये व घरेलू किसानों की आजीविका सुरक्षित करना मुश्किल हो रहा था।

फ्रांस अकेले अपनी फल और सब्जी की जरूरत का 71 फीसदी आयात करता है। भारत में, किसान आंदोलन 2.0 मुख्य रूप से कृषि उपज के लिए कानूनन बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग कर रहा है, और इसकी अन्य मांगों में भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से हटने के लिए कहना भी शामिल है।

इस लेख में अमेरिका द्वारा हाल ही में अपनाए गये उस कड़े कदम का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायेगा जो विकासशील देशों में बाजार की पकड़ और ज्यादा मजबूत करने को लेकर है। अमेरिका की तो हमेशा से विकासशील देशों के बाजार में पहुंच बनाने की तीव्र इच्छा रही है। जिसमें ध्यान का केंद्र स्वाभाविक तौर पर भारत का विशाल बाजार रहा है।

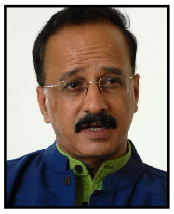

अमेरिका ने बार–बार कहा है कि भारत किसानों को उत्पाद–विशेष के लिए समर्थन की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक एमएसपी भुगतान करके डब्ल्यूटीओ की शर्तों का उल्लंघन करता है।

– देविन्दर शर्मा

अमेरिकी वित्त समिति की हालिया सुनवाई में, सीनेटरों के सवालों का जवाब देते हुए, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कैथरीन टाई ने कहा–'हम कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी परिवारों और समुदायों, विशेष रूप से हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए बाजार खोल रहे हैं। बातचीत के माध्यम से, हमारे प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों में नए कृषि बाजारों तक 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पहुंच सुनिश्चित की है,' और आगे कहा, 'इसमें वृद्धिमान बाजार, भारत के साथ 12 टैरिफ श्रेणियां शामिल हैं जो अमेरिकी निर्यातकों के लिए तरक्की का मौका हैं।'

हालांकि मेहनतकश अमेरिकी परिवारों और ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की रुचि समझी जा सकती है लेकिन भूमंडलीकरण के तहत हर देश को उन दसियों हजारों किसानों की आजीविका की भी रक्षा करनी चाहिए जो दुनिया के किसी और हिस्से में सस्ते आयातों के चलते तबाह हो जाते हैं। यह न भूलें कि भोजन का आयात करना बेरोजगारी का आयात करने के समान है।

मुझे याद है कि मैंने जर्मन किसानों से भी कमोबेश इसी तरह का प्रश्न पूछा था, जो दक्षिणी जर्मनी के लैंड्सफुहल में एक फार्म हाउस में डिनर के दौरान जीएटीटी निर्यातकों के एक छोटे समूह से मिलने आए थे (मेरी पुस्तकः गैट टू डब्ल्यूटीओ : निराशा के बीज 1995. कोणार्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली)। यह 1990 के दशक के मध्य में किसी समय का वाकया

है। 'मानता हूं कि आप सरप्लस खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं जिसके लिए आप दक्षिण में एक स्थाई बाजार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन शायद आपको इस बात का अहसास नहीं है कि आप यहां जो सरप्लस अनाज पैदा करेंगे, वह भारत जैसे देशों में लाखों छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों से दूर कर देगा। उन व्यापार वार्ताकारों के उलट, जो नष्ट हो रही कृषि आजीविका के बारे में दूर–दूर तक चिंतित हुए बिना, आजकल व्यापार वार्ता की अगुवाई करते हैं, मुझे वहां किसानों से जो उत्तर मिला, वह अत्यधिक समर्थन प्रदान करने वाला था। भारतीय किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका अधिशेष खाद्यान्न भारत में आजीविका को नष्ट कर देगा। जर्मनवासी किसान भारतीय किसानों की पीड़ा को समझ सकते थे और इसलिए चाहते थे कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

मैंने सोचा कि अमेरिका को भी उस असर का आकलन करना चाहिये जो बादाम, अखरोट और सेब समेत अन्य चीजों पर प्रतिरोधात्मक आयात शुल्क वापस लेने के बाद भारत पर पड़ेगा। चलो यहां सेब की बात करते हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 20 फीसदी आयात शुल्क वृद्धि वापस लेने के बाद जब पहली खेप भारत के लिए रवाना हुई तो सिएटल बंदरगाह पर उत्सव मनाया गया। जाहिर है, भारत वाशिंगटन के सेब के लिए 120 मिलियन डॉलर का बाजार प्रदान करता है, जिससे अमेरिका में 68,000 सेब उत्पादक किसानों को लाभ होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2023 में आयात शुल्क आंशिक रूप से वापस लेने के एक महीने के भीतर 19.5 मिलियन डॉलर मूल्य के वाशिंगटन सेब भारत भेजे गए।

जैसा कि उम्मीद थी, यूएस कांग्रेस की सुनवाई में एक सीनेटर को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि भारतीय गेहूं सब्सिडी कीमतों को बिगाड़ रही है और इससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। एक अन्य सीनेटर ने चावल सब्सिडी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगर चावल सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के मापदंडों के भीतर होती, तो इससे अमेरिकी धान किसानों के लिए 850 मिलियन डॉलर के व्यापार के अवसर खुल जाते। यदि आपका अंदाजा सही है, तो ये सीनेटर भारत में एमएसपी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत खासकर पंजाब और हरियाणा में गेहूं और चावल उत्पादक किसान, उच्च सुनिश्चित कीमतों से लाभान्वित होते हैं। अमेरिका ने बार–बार कहा है कि भारत किसानों को उत्पाद–विशेष के लिए समर्थन की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक एमएसपी भुगतान करके डब्ल्यूटीओ की शर्तों का उल्लंघन करता है।

आश्चर्यजनक तौर पर, ये आक्षेप बार–बार उस देश द्वारा लगाये जाते हैं जो दुनियाभर के कपास उत्पादकों को हानि पहुंचाने के लिए अपने देश के कपास उत्पादकों को दी जाने वाली भारी–भरकम सब्सिडी को बंद करने में विफल रहा हो। जरा तुलना ही करें तो, नई दिल्ली स्थित डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र के अनुसार, अमेरिका अपने 8,100 कपास उत्पादकों को प्रति किसान 117,494 डॉलर की घरेलू मदद प्रदान करता है। इसके विपरीत, 9 मिलियन से अधिक संख्या वाले भारतीय कपास उत्पादकों को प्रति किसान मामूली 27 डॉलर मिलते हैं। अमेरिका द्वारा अपने किसानों को प्रदान की जाने वाली कपास सब्सिडी का विवादास्पद मुद्दा पश्चिमी अफ्रीका के देशों और भारत में लाखों कृषकों की आजीविका को खत्म करने के लिए जाना जाता है, साल 2003 में असफल कैनकन डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आने के वक्त से अनसुलझा बना हुआ है।

मुझे यह भी अजीब लगता है कि जब अमेरिकी सीनेटर उस हालात में भारत के झींगा उद्योग में बाल मजदूरी पर सवाल उठाते हैं जब अमेरिकी कृषि क्षेत्र सैकड़ों की तादाद में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त करने के लिए जाना जाता है, और कुछ तो 10–12 वर्ष की नाजुक उम्र में वाणिज्यिक फार्म्स में श्रम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की तरह, मैं भी संसार में कहीं भी खेती के काम में बालश्रम का विरोधी हूं। लेकिन जब खेती के कार्य में बाल श्रमिकों को लगाने की बात आती है तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं। यह निष्पक्ष स्थिति नहीं जो स्वतंत्र व्यापार सुनिश्चित करती हो। फ्री ट्रेड का अपने आप में यह मतलब नहीं कि यह 'फेयर और लवली' है।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/the-free-trade-formula-is-like-a-clampdown-on-farmers/

समृद्धि स्वदेश में, फिर क्यों जा रहे परदेस में?

जब हम भारत की समृद्धि, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चुनौती पर विचार करते हैं तो सबसे पहले यही चिंता होती है कि हमारे लाखों उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र, कुशल कारीगर, युवा अपने देश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और जो जनसांख्यिकीय लाभ अपने देश को होना चाहिए था वह विदेशों विशेषकर अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों, आस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों को हो रहा है। यह आंकड़ों का विषय नहीं है फिर भी विदेश मंत्रालय के अनुसार 3.21 करोड़ भारतीय विदेशों में बसे हैं जिनमें 1.34 करोड़ भारतीय अनिवासी भारतीय (एन आर आई) हैं और 1.87 करोड़ भारतीय विदेशी नागरिक (ओ सी आई) है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ही 13.24 लाख भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए गये हैं। यह सभी भारतीय सुंदर सपने सजाकर विदेश गये थे।

पिछले दिनों समाचार पत्रों और मीडिया में चिंता जनक समाचार प्रकाशित हुए। वैसे तो भारतीय छात्रों पर यदा–कदा नस्ली हमले होने, भारतीय छात्रों की हत्या किये जाने के समाचार आते हैं। परंतु हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों में भारतीय छात्रों के उच्च डिग्रियों के बावजूद नौकरी और इंटर्नशिप का अभाव हो गया है। विश्व के विकसित देशों में भी आंतरिक असमानताएं व्याप्त हो रही हैं और उन देशों में नियोक्ताओं, विश्वविद्यालयों, सरकारों और कंपनियों में विदेशी छात्रों के मुकाबले अपने ही देश के युवाओं को नौकरी देने का दवाब है। अमेरिका में आठ विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित आई वी लीग समूह (हारवर्ड, येल, पेंसिलवानिया, यूसी बर्कले, ब्राउन, टेक्सास आदि) में भी उच्च डिग्री धारक छात्रों को इंटर्नशिप पाने के लिए भी निराश होना पड़ रहा है। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम टैक्नोलॉजी के छात्रों को भी निराशा हाथ लगी है। देश के राष्ट्रीय स्तर के

रोजगार सृजन और शिक्षा एक दूसरे का साथ पकड़ कर चलते हैं। विदेशों में पढ़ रहे युवाओं को अपने देश की समृद्धि पर विश्वास बढ़ेगा तो ब्रेन ड्रेन भी ब्रेन गेन में अपने आप बदलेगा।

–विनोद जौहरी

समाचार पत्रों में अमेरिका को विदेशी छात्रों के लिए सबसे अधिक प्रतिष्ठा माना जाता है और 77 प्रतिशत छात्रों की यही मान्यता है। उसके बाद पश्चिमी यूरोप के विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठता के लिए 66 प्रतिशत भारतीय छात्रों की मान्यता है। सिंगापुर और चीन भी भारतीय छात्रों का आकर्षण रहे हैं। परंतु वास्तविकता अब बदल रही है। फिर भी त्रासदी यह है कि अमेरिका और अन्य देश जहां विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं, भारत और अन्य देशों के छात्रों को अमेरिकी विश्विद्यालयों में पढ़ने के लिये लुभावने प्रयास निरंतर करते हैं। हमारे देश में बड़े महानगरों, कोचिंग मंडियों और छोटे शहरों में भी लोकल एजेंट भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के विज्ञापन, काउंसलिंग लगातार करते रहते हैं। भारत में सभी बड़े महानगरों में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं।

मेरा स्वयं का अनुभव है कि मेरे एक परिचित परिवार की बेटी आर्कीटेक्चर में आस्ट्रेलिया से ही डबल ग्रेजुएशन, डबल पोस्टग्रेजुएशन और पीएचडी करने के बाद रिसर्च एसिस्टेंट का काम कर रही हैं जिनको योग्यता के अनुसार भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हो सकती थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। भविष्य की संभावनाएं भी बहुत आशाजनक नहीं हैं।

यह कहना कि भारत में उच्च शिक्षा महंगी है, उससे कहीं अधिक विदेशों में शिक्षा महंगी है। विदेशों में रहकर पढ़ाई करना बहुत महंगा होता जा रहा है। कमरे, होस्टल का किराया बहुत बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त भोजन, लोकल आवागमन भी बहुत महंगे हो गये हैं।

अभी हाल ही में अमेरिका में विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इज़राइल के पक्ष और विपक्ष में छात्रों में झड़पें और आंदोलन हुए हैं और अराजकता फैली है। अमेरिका में विदेशी छात्रों का पच्चीस प्रतिशत भारतीय छात्रों का है और कमोबेश यही स्थिति अन्य देशों के विश्विद्यालयों में है। यह बात तो समझ आती है कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, पाकिस्तान, ट्यूनिशिया, अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, तुर्किये के छात्रों का अपने देशों में भविष्य नहीं है और चीन के छात्र पढ़ाई के चीन वापस जाना नहीं चाहते लेकिन भारत में तो अपार संभावनाएं हैं और संभ्रांत, व्यापारी वर्ग और धनाढ्य परिवारों के छात्र विदेशों में पढ़ने जायें, यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती। भारत में नौकरी के स्थान पर व्यापार से ही समृद्धि है और सरकार एवं उद्योग जगत इसके सदा तत्पर रहता है।

विदेशों में अधिक आवश्यकता छोटे और मझोले कामगारों जैसे ड्राइवर, मैकेनिक, प्लंबर, श्रमिकों आदि की है और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए बहुत संघर्ष है। परंतु इन कामगारों की स्थिति भी दयनीय है। अपने देश को कुशल कामगारों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों, डाक्टरों और प्रबंधन विशेषज्ञों की।

यदि 13.24 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं तो यह प्रश्न तो सामान्यतः उठता है कि क्या उन 13.24 लाख छात्रों को भारत में विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने की कालेजों में पठन–पाठन क्षमता है? यह प्रश्न भी विदेशी चकाचौंध से आकर्षित युवा पूछते हैं। निश्चित रूप से भारत के विश्वविद्यालयों में 4. 14 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं और यह पिछले वर्ष से 29 लाख बढ़ी है। भारत में 23 आई.आई.टी., 31 एन.आई.टी., 25 आई.आई.आई.टी., 93 निजी इंजीनियरिंग कालेज, 387 मेडिकल

विदेशों में अधिक आवश्यकता छोटे और मझोले कामगारों जैसे ड्राइवर, मैकेनिक, प्लंबर, श्रमिकों आदि की है और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए बहुत संघर्ष है। परंतु इन कामगारों की स्थिति भी दयनीय है। अपने देश को कुशल कामगारों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों, डाक्टरों और प्रबंधन विशेषज्ञों की।

कॉलेज और 7395 प्रबंधन कालेज हैं। यह तो केवल बानगी है। भारत में विश्व भर में प्रतिष्ठित बहुत से निजी विश्वविद्यालय हैं। इसलिए भारत की उच्च शिक्षा की क्षमता इतनी है कि विदेशी आकर्षण से अभिभूत छात्रों के लिए योग्यता के अनुसार पर्याप्त प्रवेश अवसर उपलब्ध हैं और उज्जवल भविष्य भी।

भारत में मुक्त व्यापार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने भारत के विदेशी विश्वविद्यालयों और काम कर रहे युवाओं को भारत के प्रति आकर्षण का शुभारंभ किया है और यह प्रक्रिया शीघ्र ही तेजी पकड़ेगी। ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

अपने देश में नयी शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन की शीघ्रता से आवश्यकता है। उच्च शिक्षा को सरकारी सहायता की आवश्यकता है जिससे मेधावी छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रोजगार सृजन और शिक्षा एक दूसरे का साथ पकड़ कर चलते हैं। विदेशों में पढ़ रहे युवाओं को अपने देश की समृद्धि पर विश्वास बढ़ेगा तो ब्रेन ड्रेन भी ब्रेन गेन में अपने आप बदलेगा। ❑❑

रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून

आज पूरी दुनिया में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। पानी के जानकार लोग तो यहां तक कह रहे हैं की दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध पानी पर ही होगा। पानी का कई प्रकार से क्षय किया जा रहा है। भारत में बहुफसली खेती की परंपरा रही है लेकिन अधिक पानी वाली फसलों को प्रोत्साहित करने का चलन चल गया है। मुख्य रूप से धान, गन्ना और गेहूं अधिक पानी वाली फैसले हैं पर अत्यधिक कमाने की होड़ में इसकी खेती बड़े रकबे में हो रही है। इसी तरह चमड़े आदि के निर्यात से भी पानी का नुकसान हो रहा है। भारत अधिकांश चीजों का निर्यात कर रहा है लेकिन दृश्य निर्यात के साथ–साथ अदृश्य पानी का भी निर्यात हो रहा है जो की आने वाले दिनों में हमारे लिए जल संकट की स्थिति खड़ा कर सकता है।

सरकार ने यूरिया–डीएपी पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष सबसिडी दी, जिससे खेती में धान और गेहूं का रकबा इस साल बढ़ गया। ये फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज्यादा निर्यात होता है। किसान बहुफसलीय खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इस वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करने पड़ते हैं। इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी भी खर्च होती है। यही नहीं, गेहूं, धान जैसी फसलों को पैदा करने में पानी के प्रबंधन और बिजली व्यवस्था में जो धन खर्च होता है, वह भी परोक्ष निर्यात के जरिए नुकसान का सबब बन रहा है। पर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस हकीकत का न तो खुलासा होता है और न ही विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाता है।

खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा यह ऐसा मुद्दा है, जिसकी अनदेखी के चलते पानी का बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है। इस पानी को 'वर्चुअल वाटर' भी कह सकते हैं। दरअसल, भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते–चप्पल, फल और सब्जियां निर्यात होते हैं। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहां बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वे भी इस पानी

जीवन में पानी का बहुत महत्व है। जल है तो जीवन है। इसलिए जनजीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि पानी के किसी भी तरह के अपव्यय को रोका जाना चाहिए।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

को बड़ी मात्रा में अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह निर्यात किए जा रहे पानी पर कालांतर में लगाम नहीं लगाई गई, तो पानी का संकट और बढ़ेगा। जबकि देश के तीन चौथाई घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं।

आमतौर पर यह भुला दिया जाता है कि शुद्ध पानी, तेल और लोहे जैसे खनिजों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में बीस हजार डालर प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक योगदान करता है। इस दृष्टि से भारत से औद्योगिक और कृषि उत्पादों के जरिए पानी का जो परोक्ष पानी का निर्यात हो रहा है, वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही प्रकार के जल भंडारों का दोहन करने का बड़ा सबब बन रहा है। दरअसल, एक टन अनाज उत्पादन में एक हजार टन पानी की जरूरत होती है। चावल, गेहूं, कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा पानी धान पैदा करने में खर्च होता है। पंजाब में एक किलो धान पैदा करने में 5,389 लीटर पानी लगता है, जबकि इतना ही धान पैदा करने में पश्चिम बंगाल में करीब 2,713 लीटर पानी खर्च होता है। पानी की इस खपत में इतना बड़ा अंतर इसलिए है, क्योंकि पूर्वी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में तापमान अधिक रहता है। खेत की मिट्टी और स्थानीय जलवायु भी पानी की कम–ज्यादा खपत से जुड़े अहम पहलू हैं। इसी तरह चीनी के लिए गन्ना उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी लगता है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए भी तीन से चार मर्तबा सिंचाई करनी होती है।

सबसे ज्यादा, सत्तर प्रतिशत पानी सिंचाई में खर्च होता है। उद्योगों में बाईस फीसद और पीने से लेकर अन्य

सिंचाई के मौजूदा संसाधन और तकनीकों से सिंचाई में करीब पच्चीस से चालीस फीसद पानी ही वास्तविक रूप में काम आता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। मगर अब बदलते परिदृश्य में फव्वरों, बूंद और स्प्रिंकलर तकनीकों को अपनाने की जरूरत है।

घरेलू कार्यों में आठ फीसद जल खर्च होता है। मगर नदियों और तालाबों की जल संग्रहण क्षमता लगातार घटने और सिंचाई तथा उद्योगों के लिए दोहन से सतह के ऊपर और नीचे जल की मात्रा लगातार छीज रही है। ऐसे में फसलों के रूप में जल का हो रहा अदृश्य निर्यात समस्या को और विकराल बनाने का काम कर रहा है।

इसे रोकने के लिए फसल प्रणाली में व्यापक बदलाव और सिंचाई में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है। ऐसा अनुमान है कि धरती पर 1.4 अरब घन किमी पानी है। लेकिन इसमें से महज दो फीसद पानी पीने और सिंचाई के लायक है। इससे जो फसलें और फल–सब्जियां उपजती हैं, उनके निर्यात के जरिए पच्चीस फीसद पानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में खपत हो जाता है। इस तरह 1,050 अरब वर्ग मीटर पानी का परोक्ष कारोबार होता है। एक अनुमान के मुताबिक इस वैश्विक धंधे में लगभग दस हजार करोड़ घन मीटर वार्षिक जल भारत से फसलों के रूप में निर्यात होता है। जल के इस परोक्ष व्यापार में भारत दुनिया में अव्वल है। खाद्य पद्वार्थों, औद्योगिक उत्पादों और चमड़े के रूप में यह निर्यात सबसे ज्यादा होता है।

कई देश पानी के इस निर्यात से बचने के लिए उन कृषि और गैर–कृषि उत्पादों का आयात करने लगे हैं, जिनमें पानी अधिकतम खर्च होता है। उन्नत सिंचाई की तकनीक के लिए दुनिया में पहचान बनाने वाले इजराइल ने संतरे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इस फल के जरिए पानी का परोक्ष निर्यात हो रहा था। इटली ने चमड़े के परिशोधन पर पाबंदी लगा दी है। इसके बदले वह जूते–चप्पल बनाने के लिए भारत से बड़ी मात्रा में परिशोधित चमड़ा आयात करता है। इसलिए फसल प्रणाली में बदलाव के साथ–साथ, पानी के उपयोग में दक्षता भी बढ़ाने की जरूरत है।

सिंचाई के मौजूदा संसाधन और तकनीकों से सिंचाई में करीब पच्चीस से चालीस फीसद पानी ही वास्तविक रूप में काम आता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। हमारे यहां पारंपरिक तरीकों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। मगर अब बदलते परिदृश्य में फव्वरों, बूंद और स्प्रिंकलर तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। इनसे तीस से पचास फीसद तक पानी की बचत होती है। अगर इनका विस्तार एक करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में हो जाए, तो भारत बड़ी मात्रा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले जल की बचत कर सकता है।

कुल मिलाकर जीवन में पानी का बहुत महत्व है। जल है तो जीवन है। इसलिए जनजीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि पानी के किसी भी तरह के अपव्यय को रोका जाना चाहिए। ऐसी परंपरागत खेती को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें पानी का कम से कम प्रयोग हो वही निर्यात के लालच में अधिक पानी की कीमत पर तैयार होने वाले अन्य उत्पादों से भी बचना चाहिए। इसके लिए सरकारी नीतियों के साथ–साथ नागरिकों को भी सूझबूझ का परिचय देना होगा। ❑❑

प्रकृति केन्द्रित विकास की अवधारणा

''नई जमीन नया आसमाँ बनाते हैं, हम अपने वास्ते अपना जहाँ बनाते हैं। अर्थ (पृथ्वी) का कुछ करो नहीं तो अनर्थ हो जायेगा।''

आज जब भी विकास की चर्चा प्रारम्भ होती है तब हमारा ध्यान बड़ेभवन, बड़े कारखाने, चमकदार सड़कें, उस पर दौड़ती बड़ी–बड़ी गाड़ियां, बड़े–बड़े माल्स, होटल, विश्वविद्यालय आदि की ओर जाता है और हम बड़े खुश होकर कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ रहा है, हमारा शेयर मार्केट उछाल पर है, हमारा उपभोग का स्तर बढ़ रहा है। यह सब देखकर हम खुश तो होते हैं लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यह विकास किस लागत पर हो रहा है। इसको पाने के लिए हमें क्या खोना पड़ रहा है। विकास के नाम पर हम कितना विनाश करते जा रहे हैं। प्रकृति का हम कितना शोषण कर रहे हैं। हम यह भूल गये कि मनुष्य प्रकृति का अंश है, प्रकृति का विजेता नहीं। जैसे इस सृष्टि में मनुष्य का स्थान और अधिकार है वैसे ही प्रकृति के अन्य घटक नदी, पेड़–पौधे, पर्वत, पशु–पक्षी, कीट–पतंग सभी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है ना कि उन सबके शोषण और विनाश के लिए।

हम मिल–जुलकर अपने भूगोल, अपने वनों, अपने खेतों, अपनी मिट्टी, अपनी नदियां, अपना पानी, अपने जंगल, अपने पहाड़, गोवंश, अपने खनिजों आदि को पुनः संजोने का प्रयास करें। परिश्रम पूर्वक इन समस्त प्राकृतिक सम्पदाओं को अपने सहज–स्वस्थ रूप में ले आयें तो हमारे देखते–देखते ही यह भूमि अपनी सहज उदारता से हमें पुनः समृद्ध करने लगेगी।

– प्रो. विजय वशिष्ठ

भारत में विकास का मतलब है – शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का संतुलित सुख। हम कैसा समाज चाहते हैं – क्या हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी प्रकृति का विनाश कर अपना विकास करे तथा आगे आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं करें। हम दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। वास्तविक विकास मानव केन्द्रित न होकर परिस्थितिकी केन्द्रित होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जमीन, जल, जंगल, जानवर एवं जन का परस्पर शोषण नहीं, पोषण होता रहे। व्यक्ति, समाज, देश, विश्व तथा प्रकृति के साथ तालमेल बना रहे।

आधुनिक विकास के कारण जलवायु परिवर्तन के संकट ने मानवता के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण अब ऋतुऐं भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। **बसंत का मौसम मानो गायब हो गया है।** सर्दियों से सीधे अचानक गर्मी का मौसम आ गया। बे–मौसम होने वाली वर्षा से फसलें नष्ट हो रही हैं। चेरापूंजी सूख रहा है। लद्धाख के ग्लेशियर पिघलने से वहां की झील एवं तालाबों में क्षमता से अधिक पानी भर रहा है। हिमालय के कच्चे पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखण्ड एवं रामबन (जम्मू कश्मीर) इसके उदाहरण हैं।

हम हमारे वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। इससे हवा, पानी, मिट्टी सब दूषित हो रहा है। देशभर में अनावश्यक भूमि जल का दोहन हो रहा है। हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदियां, तालाब, बांध आदि के जल भराव एवं जल प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे ज्यादा 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। भारत में लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। हमारे नदी–नाले सब प्रदूषित हो चुके हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, नभ एवं अग्नि सभी प्रदूषित हो चके हैं। आधुनिक विकास की गति यही रही तो प्रकृति का विनाश निश्चित है। कुछ लोगों की सुख–सुविधा में वृद्धि के लिए हम आम–जन जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। आज हमें भारतीय संस्कृति के आधार पर विकास का विचार करना होगा। हमारा देश समृद्धि तो चाहता है लेकिन प्रकृति का विनाश करना नहीं। *हम प्रकृति के उपासक हैं प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी को मां कहते हैं।* वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को माता माना है। इसलिए कहा *''माता भूमि अहं पुत्रो पृथ्वीयां''।*

ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वन, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण तथा सृष्टि के हर छोटे से छोटे जीव का आविर्भाव ईश्वर द्वारा किया गया है। इस अंतसम्बंध को विज्ञान बहुत समय बाद (1960 के दशक में) समझ पाया। लेकिन हमारे ऋषि–मुनियों को इस बात का ज्ञान हजार वर्ष पहले ही हो गया था। उन्होंने मनुष्य द्वारा पवित्र वनों, पर्वतों, नदियों, धरती, जल की देवता के रूप में पूजा करवाई। क्योंकि एक दूसरे के सहारे के कारण ही सब अस्तित्व में है।

प्रकृति आत्म संतुलित और आत्म निर्भर है, लेकिन इंसान के उस लालच से परेशान है, जिसे आधुनिक शिक्षा द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका कारण है – आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा का पवित्रता की भावना से परे होना। इसलिए प्रकृति को कष्ट झोलना पड़ रहा है।

आधुनिक विकास की होड़ में हमने पर्यावरण को जहरीला बना दिया। हवा, पानी, मिट्टी सबको प्रदूषित कर दिया। प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं एवं पर्यावरण संरक्षण की चर्चा भी कर रहे हैं। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। प्रकृति केन्द्रित विकास में हमें यह देखना होगा कि क्या विकास के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है या घट रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि विकास के नाम पर हम भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं। आधुनिक कृषि पद्धति के कारण लाखों हेक्टर भूमि बंजर होती जा रही है। पहले एक क्विंटल रासायनिक खाद डालकर जो उत्पादन किया जाता था, उसके लिए अब 5 क्विंटल रासायनिक खाद डालनी पड़ रही है। इससे यह स्पष्ट है कि भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है। भूमि का जल स्तर घट रहा है।

हमारे देश में वर्षा केवल 2 महीने होती है, उसमें भी भारी वर्ष केवल 15 दिन होती है। हमारे पूर्वजों ने वर्षा जल को संचित करके अदेव मातृका कृषि को जन्म दिया था। आज हम इस विद्या को भूल चुके हैं और अंधानुकरण में भू–जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप देश में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। आधुनिक विकास के नाम पर हम न केवल जल का दुरूपयोग कर रहे हैं बल्कि उपलब्धा जल को दूषित भी करते जा रहे हैं। हम जिन नदियों को मां मानकर पूजा करते हैं उन्हें ही प्रदूषित करते जा रहे हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृभणा कावेरी, आदि पवित्र नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। औद्योगिक वेस्टेज हम नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। गटर लाईन की गंदगी हम पवित्र नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं।

विकास के नाम पर हम वनों का विनाश कर रहे हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए कम से कम एक तिहाई भू–भाग पर वन होने चाहिए। भारत में इस समय केवल 17 प्रतिशत भूमि पर वन हैं। भूमि पर यदि वन कम होते हैं तो प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है परिणाम स्वरूप जीव मात्र का जीवन प्रभावित होता है। पृथ्वी पर यदि जंगल का हिस्सा घटता है तो उसे विकास नहीं कह सकते। उत्पादन के दौर में प्रदूषण का फैलाव हो रहा है। धरती में उष्णता बढ़ रही है। वातावरण गर्म हो रहा है। ओजोन की परतों में छिद्र हो रहा है। भूमि का क्षरण हो रहा है – इससे मानव जीवन दूभर बन रहा है। विकास की लालसा में हम अपने संसाधनों का आपराधिक उपयोग कर रहे हैं। हम विकास को गतिरोध में बदल रहे हैं। विकास की इस पागल दौड़ में हमने प्रकृति की मर्यादा को समाप्त कर दिया। आधुनिक विकास का परिणाम असहनीय बनता जा रहा है। पर्यावरण में हम जहर घोल रहे हैं। मानवीय जीवन विनाश की ओर बढ़ रहा है।

आज पशु–पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गयी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। बंदरों, आवारा कुत्तों, नील गाय आदि की बढ़ती संख्या मनुष्य, कृषि और बागवानी के लिए समस्या बन गयी है। गायों की संख्या घट रही है। अच्छी नस्ल की गायें लुप्त होती जा रही हैं।

आधुनिक विकास जिससे हम देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ लोगों का रहन–सहन का स्तर तो बढ़ सकता है लेकिन जीवन स्तर नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के धनवान होने से देश धनवान नहीं हो सकता। आधुनिक विकास की विचारधारा से आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, गरीबी, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्यायें बढ़ रही हैं। आज औद्योगिकरण प्रगति का मापदण्ड बन जाने के कारण विश्व संघर्ष तथा युद्ध

की ओर बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त उत्पादन की खपत अन्य देशों में करने की दौड़ से एक सीमा के बाद बाजार के लिए संघर्ष जन्म लेने लगता है जिसकी परिणिति युद्ध में होती है। हमें विकास के सिद्धान्त पर पुनर्विचार करना होगा। विकास भारतीय जीवन मूल्यों एवं संस्कृति के आधार पर करना होगा। जिसमें न्यूनतमता तो सभी को मिले लेकिन अधिकतम की भी कोई सीमा हो। हमें भोग की लालसा पर लगाम लगनी होगी। इसके लिए मन–मस्तिष्क को नियंत्रित करना होगा। इससे आंतरिक विकास होगा, उपभोग की गति कम होगी, संसाधनों के पुनर्जनन की गति तेज होगी। संसाधनों का संरक्षण होने से प्रकृति संतुलन का चक्र बिना रोक–टोक के घूमेगा। जैव विविधता बनी रहेगी, प्रदूषण नहीं होगा। अधिक उत्पादन – अधिक लोगों के द्वारा के सिद्धान्त से लोगों को रोजगार मिलेगा। उपयोग मर्यादित होने से सबकी न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी होगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

संतोषपूर्ण जीवन का विचार आज जापान में व्यवहार में दिखायी दे रहा है। इससे खुशी का स्तर बढ़ रहा है। हमारे देश में हैप्पीनेस इन्डेक्स घट रहा है। लोग ज्यादा उपभोग करके भी संतुष्ट नहीं हैं। लोगों के चेहरों पर हैप्पीनेस नहीं है। लोग जीवन को बोझ मानने लग गये हैं।

आज जापान में मिनिमलिज्म (न्यूनतमवाद) का सिद्धान्त लागू किया जा रहा है। यह विचार चल रहा है, थोड़ा है ज्यादा की जरूरत नहीं। जापान में लोग बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, ज्यादा सामान को तिलांजलि दे रहे हैं। सीमित कपड़े, न्यूनतम सामान को पसंद कर रहे हैं दिखावटी साजो सामान को लोग नापसंद करने लगे हैं।

धीरे ही सही, लेकिन पनपते रहेंगे और जीयेंगे या सर्वनाश देखते देखते मरेंगे। इन दो विकल्पों में से यदि एक को चुनना पड़े तो मानव जात पहला ही विकल्प चुनेगी। लेकिन इसके पहले यह दृष्टि पैदा होनी चाहिए जो जापान में हुई है।

अधिक ए.सी., अधिक फ्रिज, अधिक कारें, अधिक टीवी, अधिक माईक्रावेव, अधिक मकान, अधिक वेतन, अधिक व्यवसाय, अधिक जीडीपी, अधिक व्यापार, अधिक आयात–निर्यात, अधिक विदेशी मुद्रा भण्डार सब कुछ अधिक.. । फिर क्यों न होगा अधिक असंतोष, अधिक दुराचार, अधिक विषाद, अधिक कार्बन उत्सर्जन, अधिक मिलावट, अधिक भ्रष्टाचार... कैसे बच पायेगी यह पृथ्वी।

यदि हम गंभीरता से इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो हमें भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। जिनको आज जापान अपना रहा है। जापान अधिक का आनंद ले चुका है – इसके दुष्परिणाम उसने भुगते हैं। आज वह भारतीय सिद्धान्त – संतोष (संतोषी सदा सुखी) पर आ रहा है। और हम पश्चिम का अंधा–धुंध अनुसरण कर रहे हैं।

हमें इसकी शुरूआत व्यक्तिगत जीवन से करनी होगी। छोटी–छोटी चीजों को लेकर हमें जागरूक होना होगा। हमारे घरों, कार्यालयों में बेमतलब लाइट, पंखे, ए.सी. चलते रहते हैं। रसोई में लगे वाटर प्यूरीफायर से लेकर टायलेट्स में जिस तरह से पानी बहाया जाता है। हम घर में उसे नहीं रोकेंगे लेकिन सार्वजनिक मंचों पर पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी–बड़ी बातें करेंगे।

हमारे देश ने विश्व को जीवन जीने का दृष्टिकोण दिया है। संतोष को परम सुख का कारक बताया है (संतोषी सदा सुखी)। धरती को माता कहा है, जल और वन की पूजा की है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अष्टकोणी बताया है। पांच तत्वों (भूमि, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि) के अलावा मन, बुद्धि एवं अहंकार की भी गणना की गयी है। ये पांचों तत्व मिलकर मन और बुद्धि को निर्मल रखें तथा अहंकार को संयमित रखें। स्कंध पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें यमदूत प्रवेश नहीं करते। स्कंध पुराण के अनुसार किसी भी प्रकार के पेड़ को काटना निन्दनीय है। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है – अहिंसा परमो धर्मः। हमारी संस्कृति ही हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सिखाती है।

आओ हम पुनः अपने विकास मार्ग पर लौट चलें जहां सुख का मार्ग ज्यादा उपभोग नहीं बल्कि ज्यादा खुशी हो। देश में लोगों का उपभोग का स्तर तो बढ़े, लेकिन जीवन स्तर भी बढ़े। लोग प्रेम भाव से रहें। हैप्पीनेस बढ़े, लोग खुश हों।

हम मिल–जुलकर अपने भूगोल, अपने वनों, अपने खेतों, अपनी मिट्टी, अपनी नदियां, अपना पानी, अपने जंगल, अपने पहाड़, गोवंश, अपने खनिजों आदि को पुनः संजोने का प्रयास करें। परिश्रम पूर्वक इन समस्त प्राकृतिक सम्पदाओं को अपने सहज–स्वस्थ रूप में ले आयें तो हमारे देखते–देखते ही यह भूमि अपनी सहज उदारता से हमें पुनः समृद्ध करने लगेगी। हमारा देश सुखी होगा।

हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्।। की कल्पना को साकार रूप दे सकेंगे।

हमारी भगवान से प्रार्थना है – आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ, पतित पावनी, अर्हतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। हे करूणा सागर! अपनी अपार करूणा से शीघ्र ही राग–द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा, त्याग, प्रेम से परिपूर्ण हो। ❑❑

लेखक सेवानिवृत्त प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

अमेरिकी बैंक क्यों हो रहे दिवालिया?

अमेरिका में वर्ष 2023 में 3 बैंक (सिलिकन वैली बैंक, सिगनेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक) डूब गए थे एवं वर्ष 2024 में भी एक बैंक (रिपब्लिक फर्स्ट बैंक) डूब गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी केंद्रीय बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व, द्वारा ब्याज दरों में की गई वृद्धि के चलते बैंकों के असफल होने की यह परेशानी बहुत बढ़ गई है।

सिलिकन वैली बैंक ने कई तकनीकी स्टार्ट अप एवं उद्यमी पूंजी फर्म को ऋण प्रदान किया था। इस बैंक के पास वर्ष 2022 के अंत में 20,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सम्पत्तियां थी और यह अमेरिका के बड़े आकार के बैंकों में गिना जाता था और हाल ही के समय में डूबने वाले बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जा रहा है। इसी प्रकार, सिगनेचर बैंक ने न्यूयॉर्क कानूनी फर्म एवं अचल सम्पत्ति कम्पनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रखी थीं। इस बैंक के पास वर्ष 2022 के अंत में 11,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति थी और अमेरिका में हाल ही के समय में डूबने वाले बड़े बैंकों में चौथे स्थान पर आता है। 31 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की कुल सम्पत्तियां 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं जमाराशि 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर थीं। न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क में बैंक की 32 शाखाएं थीं जिन्हें अब फुल्टन बैंक की शाखाओं के रूप में जाना जाएगा क्योंकि फुल्टन बैंक ने इस बैंक की सम्पत्तियों एवं जमाराशि को खरीद लिया है।

पीयू रिसर्च संस्थान के अनुसार, चार शताब्दी पूर्व, वर्ष 1980 एवं वर्ष 1995 के बीच अमेरिका में 2,900 बैंक असफल हुए थे। इन बैंकों के पास संयुक्त रूप से 2.2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति थी। इसी प्रकार, वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के बीच अमेरिका में 500 बैंक, जिनकी कुल सम्पत्ति 95,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, असफल हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अमेरिका में सामान्यतः बैंक असफल नहीं

पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियां अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही हैं। अब तो अमेरिकी अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में साम्यवाद के बाद पूंजीवाद भी असफल होता दिखाई दे रहा है एवं आज विश्व को एक नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है।

– स्वदेशी संवाद

होते हैं। परंतु, इस सम्बंध में अमेरिकी रिकार्ड कुछ और ही कहानी कह रहा है। वर्ष 1941 से वर्ष 1979 के बीच, अमेरिका में औसतन 5.3 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं। वर्ष 1996 से वर्ष 2006 के बीच औसतन 4.3 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं एवं वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के बीच औसतन 3.6 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं।

वर्ष 2022 में अमेरिकी बैंकों को 62,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ था। इसके पूर्व, वर्ष 1921 से वर्ष 1929 के बीच अमेरिका में औसतन 635 बैंक प्रतिवर्ष असफल हुए हैं। यह अधिकतर छोटे आकार के बैंक एवं ग्रामीण बैंक थे और यह एक ही शाखा वाले बैंक थे। अमेरिका में आई भारी मंदी के दौरान वर्ष 1930 से वर्ष 1933 के बीच 9,000 से अधिक बैंक असफल हुए थे। इनमें कई बड़े आकार के शहरों में कार्यरत बैंक भी शामिल थे और उस समय इन बैंकों में जमाकर्ताओं की भारी भरकम राशि डूब गई थी। वर्ष 1934 से वर्ष 1940 के बीच अमेरिका में औसतन 50. 7 बैंक प्रतिवर्ष बंद किए गए थे।

अमेरिका में इतनी भारी मात्रा में बैंकों के असफल होने के कारणों में मुख्य रूप से शामिल है कि वहां छोटे छोटे बैंकों की संख्या बहुत अधिक होना है। बैंकों के ग्राहक बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं। बैंक में आई छोटी से छोटी परेशानी में भी वे बैंक से तुरंत अपनी जमाराशि को निकालने पहुंच जाते हैं, जबकि बैंक द्वारा इस राशि से खड़ी की गई सम्पत्ति को रोकड़ में परिवर्तित करने में कुछ समय लगता है। इस बीच बैंक यदि जमाकर्ता को जमाराशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार बैंक असफल हो जाता है। कई बार बैंकों द्वारा किए गए निवेश (सम्पत्ति) की बाजार में कीमत भी कम हो जाती है, इससे भी बैंकें अपने जमाकर्ताओं को जमाराशि का भुगतान करने में असफल हो जाते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में लगातार बढ़ौतरी की गई है, जिससे इन बैकों द्वारा अमेरिकी बांड में किये गए निवेश की बाजार में कीमत अत्यधिक कम हो गई है। अब इन बैंकों को बांड में निवेश की बाजार कीमत कम होने के स्तर तक प्रावधान करने को कहा गया है और यह राशि इन बैकों के पास उपलब्ध ही नहीं है, जिसके चलते भी यह बैंक असफल हो रहे हैं।

एक सर्वे में यह बताया गया है कि आने वाले समय में अमेरिका में 190 अन्य बैंकों के असफल होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ब्याज दरों के बढ़ने से ऋण की मांग बहुत कम हो गई है। विभिन्न कम्पनियों ने अपने विस्तार की योजनाओं को रोक दिया है, इससे निर्माण की गतिविधियों में कमी आई है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व, का पूरा ध्यान केवल मुद्रा स्फीति को कम करने पर है एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास दर को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादों की मांग कम हो और मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाया जा सके। इसके चलते कई कम्पनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है एवं देश में युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है।

पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियां अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही हैं। अब तो अमेरिकी अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में साम्यवाद के बाद पूंजीवाद भी असफल होता दिखाई दे रहा है एवं आज विश्व को एक नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है। इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट इशारा भारत की ओर है क्योंकि इस बीच भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित मॉडल भारत में आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल रहा है। अमेरिका में बैकों के असफल होने की समस्या मुख्यतः मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में की गई वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं। दरअसल, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्पादों की मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने के स्थान पर बाजार में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इन उत्पादों की कीमत को कम रखा जा सके। प्राचीन भारत में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण मुद्रा स्फीति की समस्या भारत में कभी रही ही नहीं है। बल्कि भारत में उत्पादों की प्रचुरता के चलते समय समय पर उत्पादों की कीमतें कम होती रही हैं। ग्रामीण इलाकों की मंडियों में आसपास ग्रामों में निवास करने वाले ग्रामीण व्यापारी एवं उत्पादक अपने उत्पादों को बेचने हेतु एकत्रित होते थे, सायंकाल तक यदि उनके उत्पाद नहीं बिक पाते थे तो वे इन उत्पादों को कम दामों पर बेचना प्रारम्भ कर देते थे ताकि गांव जाने के पूर्व उनके समस्त उत्पाद बिक जाएं एवं उन्हें इन उत्पादों को अपने गांव वापिस नहीं ले जाना पड़े। इस प्रकार भी विभिन्न उत्पादों की भारतीय मंडियों में मांग से अधिक आपूर्ति बनी रहती थी। अतः उत्पादों की कमी के स्थान पर उत्पादों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता था, इससे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मुद्रा स्फीति का जिक्र ही नहीं मिलता है। दूसरे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मॉडल एवं नियमों को बहुत जटिल बना दिया गया है। इससे भी कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही है जिसका हल विकसित देश नहीं निकाल पा रहे हैं। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी की कलम से)

रोजगार मांगने के बजाए रोजगार देने वाला बनें युवाः कश्मीरी लाल

बहराइच शहर के किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आइक्यूएसी सेल एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत डॉ. जेबी सिंह सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उद्योग केंद्र बहराइच के सहायक प्रबंधक जेपी यादव एवं महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉक्टर एसपी सिंह रहे।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कश्मीरी लाल ने विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास के क्षेत्र में स्वरोजगार तलाशने एवं आत्मनिर्भर बनने के मंत्र दिए। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के युवाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए, इस संदर्भ में उन्होंने कई प्रेरक प्रसंग को प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

विशिष्ट अतिथि जेपी यादव ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमिता विकास के क्षेत्र में संचालित स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत ही सरल रूप में विद्यार्थियों को बतलाया। बहराइच जनपद में औद्योगिक इकाइयों को और अधिक विकसित करने एवं उद्यमी बनने की उर्वरता पर भी प्रकाश डाला। महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि आज भारत का सम्मान विश्व पटल पर बढ़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में स्व रोजगार के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का युवा पीढ़ी को स्वागत करना चाहिए एवं उद्यमिता के क्षेत्र में अपना योगदान करना चाहिए।

कार्यक्रम को स्वदेशी जागरण मंच के अनुपम श्रीवास्तव तथा अजय कुमार ने संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय की एक इकाई के समन्वयक प्रोफेसर डॉ. राजबीर सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन संस्थागत नवाचार परिषद के समन्वयक डॉ. विनीत कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के बंशीधर मिश्र, राहुल सिंह, मनीष सिंह महाविद्यालय आइक्यूएसी के समन्वयक प्रो. सूर्यभान रावत, डॉ. जी. के. शुक्ला, डॉ. तबरेज अनीस, अरविंद कुमार, रुपचंद, डॉ. सी.डी. सिंह, डॉ. आशुतोष शुक्ला, डॉ. श्रेयात, डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला, डॉ शिवा चौधरी, अजय त्रिपाठी, धीरेंद्र प्रताप, अनुपम सिंह, डॉ. ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी, डॉ. अनिल अवस्थी, डॉ. राहुल सिंह, एन.सी.सी. के पंकज कुमार सिंह समेत भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

विरासत कर से धन के पलायन का खतराः डॉ. अश्वनी महाजन

भारत में चल रहे राष्ट्रीय चुनावों में विरासत कर और धन पुनर्वितरण पर एक तीव्र राजनीतिक बहस देखी जा रही है, जो 24 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की एक टिप्पणी से शुरू हुई है। इस बहस पर जोर देते हुए, अर्थशास्त्री व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन का कहना है कि अगर सुपर–रिच पर ऐसा कर लगाया जाता है, तो भारत को विदेशी देशों से अपनी संपत्ति खोनी पड़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश और उद्यमशीलता हतोत्साहित होगी।

"वित्त प्रकृति में अत्यधिक गतिशील है। विरासत कर की प्रत्याशा में यदि लोग अपनी मृत्यु के बाद अपनी संतानों पर विरासत पर लगने वाले उच्च कर से बचने के लिए अपनी संपत्ति विदेश स्थानांतरित करते हैं, तो हम राष्ट्रीय संपत्ति को विदेशी देशों के हाथों खो देंगे। यह सबसे खराब स्थिति होगी।" डॉ. महाजन ने मनीकंट्रोल को एक साक्षात्कार में बताया।

वास्तव में भारत में विरासत कर था, जिसे 1953 में लागू किया गया था, लेकिन तीन दशक से अधिक समय तक अस्तित्व में रहने के बाद 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। डॉ. महाजन ने कहा कि जब अमीरों पर कर लगाने की बात आती है तो भारत ब्रिटेन और अमेरिका के नक्शेकदम पर नहीं चल सकता, क्योंकि भारत आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिम से अलग है। "हम भारत की तुलना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से नहीं कर सकते, जहां किसी न किसी रूप में विरासत कर लगता है। वे विकसित देश हैं, लेकिन भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, इसलिए हमें 'विकसित भारत' के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्यमशीलता, बचत और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और विरासत कर जैसा उपाय इसमें मदद नहीं करता है, "अर्थशास्त्री ने कहा।

https://www.moneycontrol.com/news/business/any-inheritance-tax-in-india-risks-flight-of-wealth-from-the-country-says-economist-ashwani-mahajan-12711503.html

राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रवाद का समर्थन जरुरीः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि देश के युवा सरकारी और प्राइवेट नौकरी को अपने जीवन का ध्येय न बनाएं। वह दूसरों को नौकरी देने वाले बने। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच उनकी सहायता करेगी। उन्होंने प्रबुद्धजनों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया।

बिजनौर स्थित जैन धर्मशाला में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन और मतदाता जागरूकता गोष्ठी हुई। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने प्रबुद्ध नागरिकों को इस प्राचीन राष्ट्र भारत की आत्मा की रक्षा के लिए राष्ट्रवाद का समर्थन करने और समाज से करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय युवा सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाने को अपने जीवन का ध्येय बना लेते है और किसी कारण न मिल पाने पर निराश हो जाते है। उनको स्वाबलंबन के लिए प्रेरित करना होगा।

स्वाबलंबी भारत अभियान इसी दिशा में कार्य कर रहा है। देश भर में युवाओं का पंजीकरण किया गया है, उन्हे उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण व सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सभी मतदान जरूर करें। अध्यक्षता डॉ. अरविंद शर्मा ने और संचालन स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सहसंयोजक प्रशांत महर्षि ने किया। कार्यक्रम में विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव, प्रांत सयोजक कपिल नारंग, डॉ. प्रकाश, रामदर्शन अग्रवाल, डॉ. अवधेश वशिष्ठ, डॉ. नीरज शर्मा, सौरभ सिंघल, अजय वत्स, जितेंद्र चौधरी, मणि खन्ना, राजेश अरोड़ा, आशीष शंकर आदि उपस्थित रहे।

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/bijnor/story-support-of-nationalism-is-necessary-to-protect-the-nation-39-s-soul-kashmiri-lal-9767941.html

बेरोजगारी के मोर्चे पर राहत

चुनावी माहौल के बीच बेरोजगारी के मोर्चे पर मामूली राहत मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर 6.7 फीसदी रही जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.8 फीसदी थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेकार्यालय (एनएसएसओ) ने यह जानकारी दी है। बेरोजगारी दर को कुल श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 की मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत थी जबकि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल–जून के साथ जुलाई–सितंबर 2023 तिमाही में यह 6.6 प्रतिशत थी। दिसंबर 2023 में यह 6.5 प्रतिशत थी।

निश्चित अवधि पर होने वाले 22वें श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मुताबिक मार्च 2024 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के मामले में बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत थी। आंकड़ों से यह भी पता चला कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी–मार्च 2024 में घटकर 8.5 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.2 प्रतिशत थी। अप्रैल–जून 2023 में यह 9.1 प्रतिशत, जुलाई–सितंबर 2023 में 8.6 प्रतिशत और अक्टूबर–दिसंबर 2023 में 8.6 प्रतिशत थी।

पुरुषों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 6 प्रतिशत थी। अप्रैल–जून 2023 में यह 5.9 प्रतिशत, जुलाई–सितंबर 2023 में 6 प्रतिशत और अक्टूबर–दिसंबर 2023 में 5.8 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल भागीदारी दर मार्च तिमाही में बढ़कर 50.2 प्रतिशत हो गई। यह एक साल पहले इसी अवधि में 48.5 प्रतिशत थी। एनएसएसओ के अनुसार अप्रैल–जून 2023 में यह 48.8 प्रतिशत, जुलाई–सितंबर 2023 में 49.3 प्रतिशत और अक्टूबर–दिसंबर 2023 में 49.2 प्रतिशत थी।

https://www.livehindustan.com/business/urban-unemployment-rises-in-q4-but-more-women-join-the-workforce-detail-is-here-201715789892737.html

संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया

संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। यह मुख्य रूप से मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीली निजी खपत से प्रेरित है। इससे पहले आईएमएफ ने भी देश के विकास के पूर्वानुमान को बढ़ाया था। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं शीर्षक से अपने मिड ईयर अपडेट में पुष्टि की है कि भारत इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। वहीं, आईएमएफ ने अपने नवीनतम दृष्टिकोण में, 2024 के लिए भारत के विकास अनुमानों को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि चीन में विदेशी निवेश कम होने से भारत कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य बन गया है। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि ''काफी बेहतर'' हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को संशोधित किए जाने के मौके पर विशेषज्ञ ने यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) के आर्थिक विश्लेषण व नीति प्रभाग में वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से कहा, ''भारत को अन्य

पश्चिमी स्रोतों से भारत में आने वाले अधिक निवेश से भी लाभ हो रहा है, क्योंकि चीन में कम से कम विदेशी निवेश जा रहा है। भारत कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक निवेश स्रोत या गंतव्य बन गया है। मुझे लगता है कि इससे भारत को फायदा हो रहा है।''

वह 'वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024' के मध्य–वर्ष के ताजा अनुमानों पर जानकारी दे रहे थे। वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि संबंधी अनुमान को संशोधित किया गया है। यह अनुमान जताया गया है कि इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था लगभग सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

वर्ष 2024 के मध्य तक 'वैश्विक आर्थिक स्थिति व संभावनाओं' संबंधी जारी आंकड़ों में कहा गया, ''भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.9 प्रतिशत और 2025 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीली निजी खपत से प्रेरित है। हालांकि, कमजोर बाहरी मांग का व्यापारिक निर्यात वृद्धि पर असर जारी रहेगा, औषधि और रसायनों के निर्यात में जोरदार वृद्धि की उम्मीद है।'' मध्य वर्ष के ताजा आंकड़ों में भारत के लिए 6.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान इस साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान से अधिक है। चीन के लिए इसमें मामूली वृद्धि की गई है। अब चीन की 2024 में वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जिसका जनवरी में 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। चीन की वृद्धि दर 2023 की 5.2 प्रतिशत दर से घटकर 2024 में 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

https://www.amarujala.com/business/business-diary/united-nations-raises-india-s-2024-growth-projections-citing-strong-investment-consumption-2024-05-17

ई–कॉमर्स उद्योग में बढ़ेगी सात लाख गिग नौकरियां

साल 2023 की दूसरी छमाही में ई–कामर्स उद्योग में सात लाख गिग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि कंपनियां त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही हैं।

स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ई–कामर्स कंपनियों त्योहारी सीजन से पहले वार्षिक खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए कमर कस रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष त्योहारी सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले गिग नौकरियों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इससे संकेत मिलता है कि ई–कामर्स उद्योग परिदृश्य को लेकर काफी आशावादी है। फेस्टिव सीजन के दौरान न केवल बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे टियर–1 शहरों में गिग वर्कर्स की मांग बढ़ेगी, बल्कि वड़ोदरा, पुणे और कोयंबटूर जैसे टियर–2 और टियर–3 शहरों में भी इनकी संख्या में वृद्धि होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में वेयर हाउस संचालन, अंतिम पायदान तक डिलिवरी और कॉल सेंटर संचालन से जुड़े लोगों की मांग ज्यादा है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के वापस लौटने का अनुमान है। टीमलीज सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट बालासुब्रमण्यन का कहना है कि बीते पांच वर्षों से गिग वर्कर्स की मांग में वार्षिक आधार पर 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और यह तेजी अगले 2–3 वर्षों तक बने रहने की उम्मीद है। खासतौर पर ई–कामर्स क्षेत्र में गिग वर्कर्स की मांग बनी रहेगी।

https://www.jagran.com/business/top15-seven-lakh-gig-jobs-will-increase-in-e-commerce-industry-demand-for-temporary-employees-increased-in-festive-season-23488818.html

भारत–म्यांमार के बीच रुपये में शुरु होगा विदेशी व्यापार

म्यांमार के कॉमर्स मिनिस्टर यू आंग नाइंग ऊ ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच रुपया–क्यात व्यापार समझौता जून के अंत तक तय हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एक बार ये समझौता दोनों देशों के बीच पूरा हो जाता है तो भारत–म्यांमार के बीच व्यापार दोगुना हो जाएगा। बता दें, अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के कारण म्यांमार के पास आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। रुपया–क्यात में व्यापार करने के लिए भारत– म्यांमार के बीच स्पेशल एग्रीमेंट होना है। इसमें म्यांमार भारत को अपने सभी निर्यातों के लिए रुपये का भुगतान स्वीकार करेगा और उस रुपये के भंडार का उपयोग यहां से आयात करने के लिए करेगा।

बता दें, आरबीआई ने म्यांमार के साथ रुपये में विदेश व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को नियुक्त किया है। जहां विशेष वोस्ट्रो अकांउट खोला जाएगा। पीएनबी ने इसके लिए म्यांमार के दो बैंकों से संपर्क किया है। यू आंग नाइंग ऊ ने ईईपीसी की ओर से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में कहा कि हम 2021 से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। इस कारण से हमें दूसरे देशों के साथ डॉलर में व्यापार करने में मुश्किलों का सामाना करना पड़ रहा है। भारत पिछले वित्तीय वर्ष में म्यांमार के मुख्य व्यापारिक साझेदारों में से एक था। भारत ने अपने म्यांमार को 820 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया था और 540 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया था। भारत, म्यांमार के कुल विदेशी व्यापार का पांच प्रतिशत है। इससे पहले म्यांमार इस तरह का एग्रीमेंट चीन और थाईलैंड के साथ भी कर चुका है। ❑❑

https://www.jagran.com/business/top15-india-myanmar-rupee-kyat-trade-arrangement-by-end-of-june-myanmar-commerce-minister-u-aung-naing-oo-said-23440044.html

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

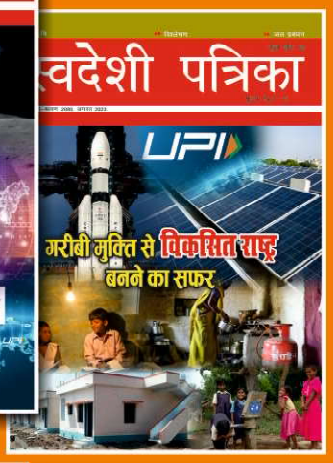

स्वदेशी
पत्रिका

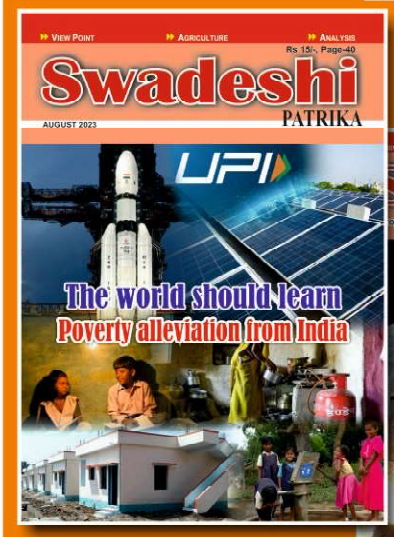

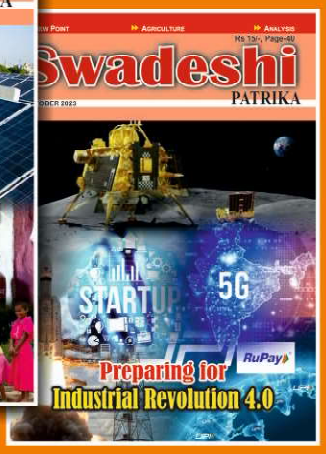

SWADESHI
Patrika

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 मई 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

बहराइच, उत्तर प्रदेश

सोलन, हिमाचल प्रदेश

बिजनौर, उत्तर प्रदेश

काशी, उत्तर प्रदेश

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती